

सामान्य समीक्षा

घटनाक्रमों की समीक्षा

वृहद आर्थिक सिंहावलोकन

अपनी उदीयमान क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए, विगत दो वर्षों में 8.5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की अभिवृद्धि के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वर्ष 2005-06 में 8.1 प्रतिशत की अभिवृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था द्वारा सतत् कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की 8.0 प्रतिशत से अधिक की अभिवृद्धि प्रलेखित इतिहास के केवल पांच वर्षों में हासिल की गई है, और इन पांच वर्षों में से दो वर्ष पिछले तीन वर्षों में से हैं। वर्ष 2004-05 में गिरकर 1.0 प्रतिशत से नीचे होने के पश्चात्, जो अधिकांशतः अनिश्चित वर्षों के कारण था, वर्ष 2005-06 में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत की अभिवृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। खरीफ की अच्छी फसल और रबी की फसल की आशाजनक संभावनाओं से वर्ष 2005-06 में, खाद्यान्न उत्पादन में 5 मिलियन टन (एम.टी.) की अभिवृद्धि होने की आशा है। हालिया वर्षों में गतिशील अभिवृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं: एक नया औद्योगिक पुनरुत्थान; निवेश में संवर्धन; वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में उत्तरोत्तर बढ़ती के बावजूद संतुलित मुद्रास्फीति; चालू लेखा घाटे के विस्तार के साथ निर्यातों और आयातों में द्रुत वृद्धि; भौतिक अवसंरचना के अपेक्षाकृत त्वरित विकास के लिए कुछ सांस्थानिक बुनियादें रखना; राजकोषीय समेकन में कुछ प्रगति; तथा समाहित अभिवृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एनआरईजी) योजना की शुरुआत।

1.2 7 फरवरी, 2006 को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 में सतत् (1999-2000) कीमतों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. की अभिवृद्धि के लिए 8.1 प्रतिशत का अग्रिम अनुमान (ईई) वर्ष 2004-05 में प्रलेखित 7.5 प्रतिशत की अभिवृद्धि से 0.6 प्रतिशतांक बिन्दु

अधिक था (सारणी 1.1)। सतत् कीमतों पर राष्ट्रीय आय के कुल योग के परिकलन के लिए सी एस ओ ने आधार वर्ष को वर्ष 1993-94 से परिवर्तित करके वर्ष 1999-2000 कर दिया है (बाक्स 1.1)। आधार वर्ष 1999-2000 के अनुसार संशोधित अभिवृद्धि दर वर्ष 2003-04 में समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए आधार वर्ष 1993-94 की दर के समरूप अथवा इससे कम है। वर्ष 2004-05 के लिए, अग्रिम अनुमान लगाते समय उपलब्ध कुछ संकेतकों के बजाय क्षेत्रक स्तर पर विस्तृत ब्यौरेवार आंकड़ों की उपलब्धता से, वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. में 7.5 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई (त्वरित अनुमान के अनुसार) जो 7 फरवरी, 2005 तथा 30 जून, 2005 के उपादान लागत पर अनुमानित स.घ.उ. के 6.9 प्रतिशत से अधिक थी।

1.3 दसवीं पंच वर्षीय योजना (वर्ष 2002-03 से वर्ष 2006-07) में परिकल्पित 8.0 प्रतिशत की वार्षिक औसत अभिवृद्धि दर की तुलना में, वर्ष 2005-06 में समाप्त होने वाले प्रथम चार वर्षों में औसत दर 7.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। योजना के प्रथम वर्ष (जिसमें 3.8 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अत्यंत निम्न वृद्धि हुई थी) को अलग करने पर प्रथम चार वर्षों में से शेष तीन वर्षों में परिणामी औसत अभिवृद्धि दर 8.0 प्रतिशत है। वर्ष 2006-07 में 8 प्रतिशत की अथवा इससे अधिक की अभिवृद्धि कायम रखने पर योजनावधि के लिए कम से कम 7.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक अभिवृद्धि दर हासिल होगी।

1.4 पिछले तीन वर्षों के लिए अभिवृद्धि रुझान वर्ष 2003-04 से अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से चक्रीय उत्थान के एक नए चरण की शुरुआत को निर्दिष्ट करता है। वर्ष 2003-04 में विस्तार के इस नए चरण को आरम्भिक संवेग कृषि द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 2004-05 में कृषिय क्षेत्रक से कुछ कुछ अवमंदित प्रोत्साहन के कारण वर्ष

सारणी 1.1 : मुख्य संकेतक

मर्दे	संपूर्ण मूल्य				पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन			
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
सकल घरेलू उत्पाद (उपादान लागत पर) (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	2255.6	2543.4 पी	2843.9क्यू	3200.6 ए	7.5	12.8 पी	11.8क्यू	12.5 ए
1999-2000 की कीमतों पर	2052.6	2226.0 पी	2393.7क्यू	2586.6 ए	3.8	8.5 पी	7.5क्यू	8.1 ए
सकल घरेलू उत्पाद-कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रक (हजार करोड़ रुपए)								
(1999-2000 की कीमतों पर)	448.7	493.7 पी	497.4क्यू	508.6 ए	-6.9	10.0 पी	0.7क्यू	2.3 ए
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (उपादान लागत पर) (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	2238.9	2525.1 पी	2826.0क्यू	3178.8 ए	7.8	12.8 पी	11.9क्यू	12.5 ए
1999-2000 की कीमतों पर	2033.8	2208.2 पी	2376.7क्यू	2566.8 ए	3.9	8.6 पी	7.6क्यू	8.0 ए
कृषि उत्पादन का सूचकांक (1)	150.4	181.0	179.2 पी	—	-15.9	20.3	-1.0क्यू	—
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	174.8	213.5	204.6 +	209.3++	-17.9	22.1	-4.2क्यू	2.3++
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2)	176.6	189.0	204.8	215.4 ^	5.8	7.0	8.4	7.8 ^
उत्पन्न बिजली (बिलियन के.डब्ल्यू.एच. में)	531.6	558.3	587.4	458.6 ^	3.2	5.0	5.2	4.7 ^
शोक मूल्य सूचकांक (3)	172.3	180.3	189.5	196.2 #	6.5	4.6	5.1	4.1 #
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (4)	487	504	525	550 \$	4.1	3.5	4.2	5.6 \$
मुद्रा आपूर्ति (एम 3)(5) (हजार करोड़ रुपए)	1718.0	2005.7	2250.4	2551.9(6)	14.7	16.7	12.2	16.4(6)
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	2,97,206	3,59,108	4,90,532	4,81,339***	21.2	20.8	36.6	24.1***
(मिलियन अमरीकी डालर)	61,412	78,149	1,09,173	1,08,803***	19.4	27.3	39.7	26.7***
वर्तमान कीमतों पर निर्यात (करोड़ रुपए)	2,55,137	2,93,367	3,61,879	3,31,771***	22.1	15.0	23.4	16.5***
(मिलियन अमरीकी डालर)	52,719	63,843	80,540	74,978***	20.3	21.1	26.2	18.9***
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (7) (करोड़ रुपए)	3,41,476	4,66,215	5,93,121	5,89,526 *	37.1	36.5	27.2	9.1 *
(मिलियन अमरीकी डालर)	71,890	1,07,448	1,35,571	1,33,770 *	40.8	49.5	26.2	8.2 *
विनिमय दर (रुपए/अमरीकी डालर) (8)	48.40	45.95	44.93	44.25 @	-1.5	5.3	2.3	2.1 @

टिप्पणी : सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े उपादान लागत के अनुसार हैं (नई शृंखला आधार वर्ष 1999-2000)

क्यू-त्व्रित अनुमान ए-अग्रिम अनुमान पी-अनन्तिम @ अप्रैल-जनवरी 2005-06 के लिए औसत विनिमय दर

* जनवरी 2006 के अंत में ** दिसम्बर 2004 के अंत में *** अप्रैल-जनवरी 2005-06,

4 फरवरी, 2006 के अनुसार # दिसम्बर, 2005 के अनुसार + चौथा अग्रिम अनुमान 2004-05

^ अप्रैल-दिसम्बर, 2005 ++ दूसरा अग्रिम अनुमान 2005-06

1. कृषि उत्पादन का सूचकांक (46 फसलों का, रोपण फसलों सहित) आधार 1981-82 को समाप्त त्रय वर्ष = 100 (संशोधित)
2. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, (आधार 1993-94 = 100)
3. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1993-94 = 100)
4. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1982 = 100)
5. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।
6. 20 जनवरी, 2006 को वर्षानुवर्ष वृद्धि (11 अक्टूबर, 2004 से एक गैर बैंकिंग कम्पनी के बैंकिंग कम्पनी में रूपांतरण को घटाकर)।
7. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।
8. प्रतिशत परिवर्तन अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की मूल्यवर्धन दर (+)/ह्रास (-) को निर्दिष्ट करता है।

बाक्स 1.1 : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, जिसे राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करने व उन्हें जारी करने के लिए अधिदेशित किया गया है, वर्ष 1956 में आधार वर्ष 1948-49 के अनुसार राष्ट्रीय आय के पहले अधिकारिक अनुमान तैयार किए थे। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए, आधार वर्ष अब तक 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1993-94 और 1994-2000 में पांच बार बदला गया है।

अद्यतन आधार वर्ष 1999-2000 का चयन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा रोजगार और बेरोजगारी संबंधी पंचवर्षीय सर्वेक्षण के 55वें दौर के वर्ष से सुमेल हो रहा है। एनएसएसओ के क्रमशः असंगठित विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों व आवासीय स्थितियों के 56वें, 57वें और 58वें दौरों के सर्वेक्षणों का प्रयोग करने के अतिरिक्त, 1999-2000 की नई श्रृंखला में अखिल भारत पशुधन जनगणना, 2003, जनसंख्या जनगणना, 2001 और अखिल भारत लघु उद्योग जनगणना 2001-02 का प्रयोग भी किया गया है। विस्तार के व्यापक होने, प्रक्रियाओं में सुधार और दीर्घावधिक सर्वेक्षण परिणामों के सम्मिलन से, आधार वर्ष में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नई श्रृंखला के अनुसार संघण्ड के अनुमानों में कुछ परिवर्तन हुए हैं।

उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद : नई तथा पुरानी श्रृंखला

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वर्तमान कीमतों पर			सतत् कीमतों पर			
	नई श्रृंखला	पुरानी श्रृंखला	प्रतिशत परिवर्तन	नई श्रृंखला	पुरानी श्रृंखला	प्रतिशत वृद्धि	
	आधार वर्ष 1999-2000	आधार वर्ष 1993-94		आधार वर्ष 1999-2000	आधार वर्ष 1993-94	नई श्रृंखला	पुरानी श्रृंखला
1999-2000	17,92,292	17,61,838	1.7	17,92,292	11,48,367		
2000-01	19,30,184	19,02,999	1.4	18,70,388	11,98,592	4.4	4.4
2001-02	20,97,446	20,81,474	0.8	19,78,056	12,67,945	5.8	5.8
2002-03	22,55,574	22,54,888	0.0	20,52,586	13,18,362	3.8	4.0
2003-04	25,43,396	25,19,785	0.9	22,26,041	14,30,548	8.5	8.5
2004-05	28,43,897	28,30,465	0.5	23,93,671	15,29,408	7.5	6.9

आधार वर्ष में परिवर्तन के साथ सतत् कीमतों (1999-2000) पर संघण्ड की समग्र अभिवृद्धि दरों में कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुए हैं यद्यपि, क्षेत्रक स्तर पर अभिवृद्धि दरों में परिवर्तन हुए हैं।

2005-06 में कृषि अभिवृद्धि में संतुलित सुधार आया है (सारणी 1.2)। यह अंशतः वर्षा की पद्धति के अनिश्चित से परिवर्तित होकर लगभग सामान्य वितरण होने के कारण है।

1.5 कृषि में तीव्र उतार चढ़ाव के एकदम विपरीत, उद्योग एवं सेवाओं में सुस्थिर विस्तार होना जारी रहा है। वस्तुतः वर्ष 2002-03 में दसवीं योजना के आरम्भ होने के समय से 7.0 प्रतिशत या अधिक की वार्षिक अभिवृद्धि के साथ (सारणी 1.2), उद्योग तथा सेवाओं ने अर्थ व्यवस्था की समग्र अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले जुड़वा ईंजनों के रूप में कार्य किया है। एक अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि में, वर्ष 2000-01 तथा वर्ष 2005-06 (अग्रिम अनुमान) के बीच के छः वर्षों में औसत आधार पर स.घ.उ. के 52.0 प्रतिशत के अंश के साथ सेवाओं ने स.घ.उ. की अभिवृद्धि में

65.0 प्रतिशत का योगदान दिया, तथा स.घ.उ. में इसका हिस्सा 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 54.1 प्रतिशत हो गया। इसी संदर्भ अवधि के दौरान औसत आधार पर स.घ.उ. में 25.8 प्रतिशत के अंश के साथ उद्योग द्वारा स.घ.उ. की अभिवृद्धि में 28.0 प्रतिशत का योगदान करने से स.घ.उ. में इसका हिस्सा 25.9 प्रतिशत से बढ़कर 26.2 प्रतिशत हो गया।

1.6 वर्ष 2002-03 की दूसरी तिमाही से आरम्भ समग्र औद्योगिक सुधार जारी है। वर्ष 1999-2000 की सतत् कीमतों पर उपादान लागत पर औद्योगिक स.घ.उ. की त्वरित अभिवृद्धि जो वर्ष 2002-03 में 7.0 प्रतिशत से बढ़कर अगले दो वर्षों में 7.6 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत हो गई, के पश्चात, औद्योगिक पुनरुत्थान इस की अभिवृद्धि के बढ़कर चालू वर्ष में

सारणी 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद में उपादान लागत पर क्षेत्रक वास्तविक वृद्धि दरें
(1999-2000 कीमतों पर)

संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन					
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (पी)	2004-05 (क्यू.)	2005-06 (ए)
I. कृषि एवं संबद्ध उद्योग	0.0	6.2	-6.9	10.0	0.7	2.3
II. उद्योग	6.3	2.7	7.0	7.6	8.6	9.0
खनन तथा उत्खनन	2.5	1.8	8.7	5.3	5.8	1.0
विनिर्माण	7.7	2.5	6.8	7.1	8.1	9.4
विजली, गैस तथा जलापूर्ति	2.0	1.7	4.8	4.8	4.3	5.4
निर्माण	6.1	4.0	7.7	10.9	12.5	12.1
III. सेवाएं	5.6	7.1	7.3	8.2	9.9	9.8
व्यापार, होटल, संवहन तथा संचार	7.1	9.2	9.1	12.0	10.6	11.1
वित्तीय सेवाएं	4.1	7.3	8.0	4.5	9.2	9.5
सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	4.7	3.9	3.8	5.4	9.2	7.9
IV. उपादान लागत पर कुल स.घ.उ.	4.4	5.8	3.8	8.5	7.5	8.1

पी : अनन्तितम क्यू : त्वरित अनुमान; ए : अग्रिम अनुमान
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

9.0 प्रतिशत हो जाने के अनुमान में अभिव्यक्त होता है। चालू वर्ष में, औद्योगिक अभिवृद्धि विनिर्माण तथा संरचना क्षेत्रकों से प्रभावशाली निष्पादनों द्वारा अभिप्रेरित है (सारणी 1.2)। उद्योग के अंतर्गत हालांकि विनिर्माण अभिवृद्धि वर्ष 2003-04 में 7.1 प्रतिशत से स्थिर रूप से त्वरित होकर वर्ष 2005-06 में 9.4 प्रतिशत हो गई है, संरचना अभिवृद्धि पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान द्विअंकीय रही है। आवास तथा स्थावर सम्पदा में पर्याप्त वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट का प्रवाह हो रहा है, तथा खुदरा क्षेत्रकों ने संरचना एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में उछाल को सहायता देना जारी रखा। नकारात्मक पक्ष पर, अंशतः मुम्बई हाई नार्थ प्लेटफार्म पर जुलाई 2005 में एक अग्नि दुर्घटना के परिणामस्वरूप कच्चे तेल के उत्पादन स्तरों में गिरावट के कारण खनन तथा उत्खनन की अभिवृद्धि में गिरावट का समग्र औद्योगिक अभिवृद्धि पर अवमंदनकारी प्रभाव पड़ा है।

1.7 सेवा क्षेत्रक की अभिवृद्धि व्यापकाधारित बनी रही। सेवाओं के तीन उप-क्षेत्रकों में से 'व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार सेवाएं' तीसरे अनुक्रमिक वर्ष के लिए द्विअंकीय दरों पर बढ़ती हुई अग्रणी बनी रहीं (सारणी 1.2)। रेलवे यात्री संजाल के विस्तार तथा वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में प्रभावपूर्ण प्रगति, एवं दूरभाष संयोजनों, विशेषतया मोबाइलों, के विद्यमान स्टॉक में तीव्र परिवर्धन ने ऐसी अभिवृद्धि में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। वित्तीय सेवाओं (जिनमें बैंकिंग,

बीमा तथा स्थावर सम्पदा सेवाएं शामिल हैं) में अभिवृद्धि, जो वर्ष 2003-04 में मंद होने के पश्चात अनुवर्ती वर्ष में पुनः हासिल कर ली गई थी, ने भारतीय वित्तीय बाजारों की प्रगामी परिपक्वता तथा चल रही संरचना सहसावृद्धि के साथ संवेग को कायम रखा। तथ्यपि, लोक प्रशासन एवं रक्षा समाहित सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं, जिन्होंने राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया एवं राजकोषीय व्यय प्रबंधन की बढ़ती दक्षता को प्रतिबिम्बित किया, में एक प्रतिशतांक से अधिक का अभिवृद्धि ह्रास हुआ (सारणी 1.2)।

1.8 व्यवसाय अभिवृद्धि के लिए उच्च आशावादिता को प्रतिबिम्बित करते हुए निवेश में संवर्धन ने न केवल औद्योगिक निष्पादन को सुदृढ़ किया बल्कि अभिवृद्धि दृष्टिकोण को भी पुनर्बलित किया। वर्ष 2002-03 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण में आरम्भ हुई वृद्धि जारी है। वर्ष 2002-03 में औद्योगिक सुधार के आरम्भ होने से पूर्व चालू बाजार कीमतों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सकल घरेलू पूंजी निर्माण वर्ष 1999-2000 में 26.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001-02 में 23.0 प्रतिशत हो गया था। दो अनुवर्ती वर्षों में पुनः बढ़कर 25.3 प्रतिशत एवं 27.2 प्रतिशत होने के पश्चात् यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2004-05 में 30.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

1.9 वर्ष 2004 में 11 प्रतिशत के स्टॉक बाजार सूचकांक प्रतिफल, जो वर्ष 2005 में 36 प्रतिशत हो गए थे, निवेशक

मनोभावों का एक सही आकलन उपलब्ध कराते हैं। घंटीनुमा बीएएसई सूचकांक 6 फरवरी, 2006 को 10,000 के आंकड़े को पार कर गया। वर्ष 2005 में, इक्विटी के लिए प्राथमिक बाजार से 30,325 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए गए। वर्ष 2002 से निरंतर वर्धित हो रही आरम्भिक सार्वजनिक पेशकशों की वार्षिक संख्या वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 के बीच 26 से बढ़कर 55 हो गई। निवेश में परिवर्धन के समनुरूप वाणिज्यिक क्षेत्रक को बैंक क्रेडिट में वर्ष 2004-05 के दौरान 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा मार्च 2005 तथा 20 जनवरी, 2006 के बीच इसमें 21.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.10 औद्योगिक क्षेत्र में हुए जबरदस्त विकास और कृषि क्षेत्र को मिलने वाले ऋणों में वृद्धि करने के सरकार के सुविचारित निर्णय के परिणामस्वरूप बैंक ऋण में तेजी से वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले खाद्य-भिन्न ऋण में वर्ष 2004-05 में 2,21,802 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो वर्ष 2003-04 में हुई 1,25,088 करोड़ रुपए की वृद्धि से काफी अधिक थी। वर्ष 2005-06 की अवधि (20 जनवरी, 2006 को समाप्त) के दौरान, खाद्य-भिन्न ऋण में 2,66,857 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो गत वर्ष की तदनु रूप अवधि में हुई 1,68,188 करोड़ रुपए की वृद्धि से 25.2 प्रतिशत अधिक थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए खाद्य ऋण में वर्ष 2004-05 में, गत वर्ष में हुई 13,517 करोड़ रुपए की गिरावट की तुलना में 5,159 करोड़ रुपए की वृद्धि होने के बाद, वर्ष 2005-06 के दौरान 20 जनवरी, 2006 तक पुनः 2,778 करोड़ रुपए की गिरावट हुई जिसके कारण कमी वाले कृषि वर्ष के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपेक्षाकृत कम खरीद और कम भण्डारों का होना था।

1.11 वर्ष 2004-05 के दौरान बैंक ऋणों का संवितरण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से फैला था जहां आवास और खुदरा क्षेत्र को ऋणों का प्रवाह विशेष रूप से तेज़ था और कृषि क्षेत्र को ऋण-प्रवाह में पर्याप्त उछाल आया। वर्ष 2004-05 में मजबूत औद्योगिक सुधार के साथ-साथ उद्योग (मध्यम और विशाल) को मिलने वाले ऋण में 17.4 प्रतिशत की कहीं अधिक वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष केवल 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2005-06 के दौरान, अक्टूबर, 2005 के अन्त तक, उद्योग (मध्यम एवं विशाल) क्षेत्र को मिलने वाले ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि (अक्टूबर, 2004 के अन्त की स्थिति की तुलना में) में 45.7 प्रतिशत का और त्वरण हुआ।

1.12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले उधारों में गत वर्ष के दौरान

24.7 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद वर्ष 2004-05 में 31.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल बकाया ऋण 3,45,627 करोड़ रुपए था। वर्ष 2005-06 में, अक्टूबर, 2005 के अन्त में, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में गत वर्ष की तदनु रूप तारीख के स्तर से 1,43,407 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो 49.4 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को मिलने वाला ऋण-प्रवाह मुख्यतया कृषि और “अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों से प्रेरित था। कृषि को मिलने वाला ऋण गत तीन वर्षों में मार्च, 2002 के अन्त में 60,761 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़ता हुआ मार्च, 2005 के अन्त में 1,22,370 करोड़ रुपए पर पहुंचकर दोगुने से अधिक हो गया; अक्टूबर, 2005 के अन्त में ऐसे बकाया ऋण शेष 1,41,612 करोड़ रुपए के थे।

1.13 भारत सरकार द्वारा 18 जून, 2004 को घोषित इस ‘कृषि ऋण पैकेज’ के अनुसार कि आगामी तीन वर्षों में कृषि को मिलने वाले ऋण के प्रवाह को दोगुना कर दिया जाएगा, सभी अभिकरणों ने कृषि के लिए संस्थागत ऋण का लक्ष्य वर्ष 2004-05 के लिए 1,05,000 करोड़ रुपए रखा था, जिससे गत वर्ष की उपलब्धि के स्तर से 30 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2004-05 के दौरान, कृषि क्षेत्र को 1,25,309 करोड़ रुपए का कुल संवितरण किया गया, 1,05,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से 19.3 प्रतिशत अधिक का निष्पादन हुआ और गत वर्ष की तुलना में यह 41.1 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2005-06 के दौरान, पूरे वर्ष के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2005 के अन्त तक कृषि क्षेत्र को मिला संस्थागत ऋण 1,17,899 करोड़ रुपए था जो वार्षिक लक्ष्य का 84 प्रतिशत बैठता है। लघु उद्योगों को मिलने वाला ऋण मार्च, 2002 के अन्त में 57,199 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़ता हुआ मार्च, 2005 के अन्त में 76,114 करोड़ रुपए हो गया तथा और अधिक बढ़ता हुआ अक्टूबर, 2005 के अंत में 78,780 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया।

1.14 वर्ष 2004-05 के दौरान ऋण-संयोजित 5,39,365 नए स्व-सहायता समूह (एसएचजी) की संख्या में गत वर्ष की तुलना में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा ऋण संयोजित कुल 16.18 लाख स्व-सहायता समूहों में अनुमानतः 242 लाख गरीब परिवार शामिल थे जिनमें प्रति परिवार ऋण का औसत संवितरण 3,044 रुपए था। नाबार्ड द्वारा दी गई पुनर्वित्त सहायता

3,082 करोड़ रुपए थी। इस कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता यह थी कि बैंकों के साथ संयोजित समूहों का लगभग 90 प्रतिशत केवल महिला समूहों का था। वर्ष 2005-06 के पूरे वर्ष में 3 लाख स्व-सहायता समूहों को संयोजित करने के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर 2005 तक 2.11 लाख नए स्व-सहायता समूह संयोजित किए जा चुके थे।

1.15 वर्ष 1993-94 से वर्ष 2003-04 तक, उद्योगों के निवल पूंजी स्टॉक (खनन, विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों से समाहित, तथा सतत् कीमतों पर), जो क्षमतावर्धन का प्रतिनिधित्व कर सकता है में 6.66 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर पर वृद्धि हुई। उद्योगों के प्रयोगाधारित वर्गीकरण का अनुकरण करते हुए, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में अप्रैल-दिसम्बर, 2005 में 15.7 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर ने पिछले वर्ष की समान अवधि में 13.8 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार निर्दिष्ट किया। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वर्ष 2003-04 में 40 प्रतिशत की अभिवृद्धि के पश्चात् वर्ष 2004-05 में 21 प्रतिशत की उफ्लावक अभिवृद्धि ने उच्चतर घरेलू निवेश को प्रतिबिम्बित किया। पूंजीगत वस्तुओं के आयात की वृद्धि में गैर-वैद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण, धातुओं तथा मशीन औजारों के निर्माण का प्रमुख योगदान था।

1.16 कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण विश्व के अधिकांश भागों में मुद्रास्फीति ने वृद्धिकारी रुझान दर्शाया। वर्ष 2003 की अंत-अवधि से तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र तथा उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ पर्याप्त सप्ताह-दर सप्ताह और यहां तक कि दैनंदिन उतार चढ़ाव ने बृहद् आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की। कच्चे पेट्रोलियम के भारतीय समूह की औसत प्रमुख विश्व कीमत 44.5 प्रतिशत बढ़कर अप्रैल-नवम्बर, 2004 में 37.3 अमरीकी डालर प्रति बैरल से अप्रैल-नवम्बर, 2005 में 53.9 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई तथा 13 फरवरी, 2005 को यह कीमत 58.10 अमरीकी डालर प्रति बैरल थी। फिर भी, आर्थिक अभिवृद्धि के वर्तमान प्रतिवर्तित चरण में लाभकारी विस्तार को घरेलू कीमतों में अनावश्यक कीमत वृद्धि के बिना कायम रखा गया है। भारत में, थोक मूल्य सूचकांक में बिन्दु-दर-बिन्दु वृद्धि द्वारा मापित मुद्रास्फाति 2 अप्रैल, 2005 को 5.7 प्रतिशत से गिरकर 27 अगस्त, 2005 को 3.3 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गई। उसके पश्चात् बढ़ने के बावजूद 5 फरवरी, 2005 को 5.0 प्रतिशत की तुलना में 4 फरवरी, 2006 को 4.1 प्रतिशत

की थोक मूल्य सूचकांक-मुद्रास्फीति दर के साथ कीमतों सहज स्तरों पर बनी हुई हैं।

1.17 विगत वर्ष की भांति, थोक मूल्य सूचकांक समूह में 14.2 प्रतिशत के भारांश वाले ईंधन, विद्युत, बिजली तथा स्नेहन समूह ने अर्थव्यवस्था में कीमत वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किया। 4 फरवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार, 7.6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर के साथ ईंधन समूह ने समग्र मुद्रास्फीति में 40.5 प्रतिशत का योगदान दिया जो एक वर्ष पूर्व के 42.8 प्रतिशत से मामूली रूप से कम है। ईंधन समूह में अधिकांश मुद्रास्फीति वैश्विक तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि द्वारा प्रेरित पेट्रोल एवं डीज़ल की वर्धित खुदरा कीमतों के रूप में क्रमशः जून एवं सितम्बर, 2005 में प्रभावी किए गए 'अंतरण' पर आरोप्य है। हालांकि उपभोक्ताओं पर कम भार डालने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरणीकृत केरोसीन के, तथा घरेलू एल पी जी के खुदरा मूल्यों को अपरिवर्तित रखा गया, तथापि, अपूर्ण 'अंतरण' के परिणामस्वरूप, घरेलू तेल कम्पनियों के वित्त साधनों तथा राजकोष, दोनों के लिए ऐसी कम्पनियों को 'तेल बांडों' के निर्गम के कारण प्रतिकूल निहितार्थ थे।

1.18 वर्ष 2004-05 की अंतिम तिमाही से विनिर्मित उत्पादों में अवलोकित मुद्रास्फीति अवमंदन की प्रवृत्ति जारी है क्योंकि इस समूह की मुद्रास्फीति दर एक वर्ष पहले की 4.5 प्रतिशत की दर से गिरकर 4 फरवरी, 2006 को 2.4 प्रतिशत रह गई। 1 अप्रैल, 2005 से अधिकांश राज्यों में मूल्य वर्धित कर (वैट) की शुरूआत किए जाने के फलस्वरूप थोक और खुदरा, दोनों मूल्यों में इस ह्रास से राज्य-स्तरीय बिक्री करों के मौलिक सुधार के लिए आम सहायता जुटाने में सहायता मिली है-ऐसा सुधार जिसे कुछ लोगों द्वारा स्वतंत्रता पश्च भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर सुधार कहा गया है। विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति ऐसे उत्पादों के लिए वर्धनात्मक रूप से उदारीकृत बाजारों में तीव्रतम प्रतिस्पर्धा के साथ कड़े नियंत्रणाधीन थी।

1.19 तथापि प्राथमिक वस्तुओं में पूर्ववर्ती दो वर्षों में अवलोकित निम्न मुद्रास्फीति इस समूह के लिए बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर के 5 फरवरी, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 के बीच 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.9 प्रतिशत होने के साथ साथ समाप्त हो गई। प्राथमिक उत्पादों में इस विरोधी घटनाक्रम के कारण प्याज और आलू जैसी कुछ वस्तुओं की आपूर्ति में कमी प्रतिबिम्बित हुई और पूरे विश्व में खनिजों की मांग बढ़ गई। थोक मूल्य सूचकांक समूह में 22.0 प्रतिशत के भारांश वाली प्राथमिक मर्दों ने 4 फरवरी, 2006 की समग्र मुद्रास्फीति में 26.3 प्रतिशत का

योगदान किया जो एक वर्ष पहले के 5.2 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर है। प्राथमिक खाद्य मर्दों में, आलू और प्याज के अलावा बाजरा, उड़द, चना, मूंग, कॉफी और अंतर्देशीय मत्स्य में चालू वर्ष के दौरान उच्चतर मुद्रास्फीति परिलक्षित हुई। कुछ फसलों के उच्चतर मूल्य अंशतः देश के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि के कारण हुए उत्पादन विघटनों के परिणामस्वरूप थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के समनुरूप कच्चे कपास के मूल्यों में पूर्व वर्ष में अनुभव किए गए निम्न स्तरों से कुछ सुधार हुआ। बेहतर फसल की संभावनाएं तिलहनों के मूल्य को संतुलित स्तर पर बनाए रखने में सफल रही हैं।

1.20 विनिर्माणों ने, समूह के रूप में, एक वर्ष पूर्व की 51.6 प्रतिशत की तुलना में 4 फरवरी, 2006 को 4.1 प्रतिशत की समग्र मुद्रास्फीति में 33.1 प्रतिशत का निम्नतर योगदान दिया। विनिर्माणों में, “अन्य अलौह धातुओं” में उच्चतम मूल्य वृद्धि (34.1 प्रतिशत) देखी गई जिसके बाद लकड़ी और लकड़ी उत्पादों (15.5 प्रतिशत) और रबर तथा प्लास्टिक उत्पादों (6.3 प्रतिशत) का क्रम है। विनिर्मित खंड में, घरेलू शर्करा मूल्य निःशेष होते स्टॉकों और वैश्विक मूल्यों में वृद्धि के कारण वर्धित रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार दशाओं में परिवर्तनों के प्रतिक्रिया स्वरूप घरेलू उत्पादकों द्वारा वस्तुसूची स्तरों में अक्सर परिवर्तन करने से घरेलू इस्पात कीमतों ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रतिबिम्बित करना जारी रखा। चालू वित्त वर्ष में अब तक इस्पात की कीमतों में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में संतुलित रही है। संरचना गतिविधि में तीव्र उच्छलन के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अब तक सीमेंट की कीमतों में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.21 अप्रैल 2005 में, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एल) और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के संदर्भ में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति क्रमशः 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत थी। वर्ष 2005-06 के प्रथम नौ माहों के लिए सीपीआई-एल के लिए उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सीपीआई-एल में मुद्रास्फीति, दिसम्बर 2005 के माह सहित चालू वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू में मुद्रास्फीति से कम थी। इसके अतिरिक्त, खाद्य समूह के लिए मुद्रास्फीति दर (जिसका सीपीआई में डब्ल्यूपीआई से अधिक भारांश है) समग्र मुद्रास्फीति की दर से कम रहने से अक्टूबर, 2005 तक सीपीआई मुद्रास्फीति (सीपीआई-एल तथा सीपीआई-आई डब्ल्यू दोनों के संदर्भ में मापित) डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से कम रही। सीपीआई-एल और सीपीआई-आईडब्ल्यू, दोनों में, मुद्रास्फीति ने कुछ मामूली

घट-बढ़ के साथ अप्रैल तथा अगस्त, 2005 के बीच क्रमशः 3.2 प्रतिशत तथा 3.4 प्रतिशत तक गिरने के पश्चात एक ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाई। दिसम्बर, 2005 में सीपीआई-आईडब्ल्यू में मुद्रास्फीति 5.6 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्यों में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति मुख्यतः सब्जियों और दलहनों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि होने के कारण थी।

1.22 मूल्य स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य बना रहा। इसे प्राप्त करने के लिए, अधिक निवेश और अभिवृद्धि के लिए एक समर्थकारी माहौल प्रदान करने के एक अन्य लक्ष्य के साथ-साथ, नीति परिवर्तियों को समुचित रूप से पुनः अंशांकित किया गया। हालांकि चालू वर्ष के दौरान बैंक दर और नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) क्रमशः 6.0 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहे, भारतीय रिजर्व बैंक की नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन निर्धारित प्रतिवर्ती रिपो दर में तीन बार 25 आधार बिन्दु प्रत्येक की वृद्धि की गई, जो 24 जनवरी, 2006 को 5.50 प्रतिशत पर पहुंच गई। प्रतिवर्ती रिपो दर की तुलना में 100 आधार बिन्दुओं के विस्तार से, 24 जनवरी, 2006 से रिपो दर 6.50 प्रतिशत पर कायम रखी गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत अनुक्रिया कच्चे तेल की उच्च कीमतों के बढ़ने की मुद्रा स्फीतिकारी प्रत्याशाओं की आशंका से अनेक अन्य देशों में एक मापित तरीके से ब्याज दरों के नीतिगत उतार-चढ़ाव के सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण के समनुरूप थी।

1.23 मार्चात 2005 में स्थूल मुद्रा (एम₃) में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए अपनी वार्षिक नीति विवरण में अनुमानित 14.0 प्रतिशत और मार्चात 2004 में अवलोकित 16.7 प्रतिशत की वृद्धि, दोनों से कम थी। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2004-05 के दौरान निवल घरेलू ऋण में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होने (वर्ष 2003-04 के दौरान 11.7 प्रतिशत की तुलना में 13.3 प्रतिशत) और बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने (वर्ष 2003-04 के दौरान 33.7 प्रतिशत की तुलना में 23.3 प्रतिशत) से एम₃ के स्रोतों की वृद्धि में कुछ विविधता आई। वर्ष 2004-05 में अधिकांश निवल घरेलू ऋण विस्तार वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में वृद्धि (22.8 प्रतिशत) के कारण हुआ हालांकि सरकार को निवल बैंक ऋण में केवल 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्चात 2005 की तुलना में 20 जनवरी, 2006 को एम₃ में पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में अवलोकित 9.2 प्रतिशत की तुलना में 13.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई।

20 जनवरी, 2006 को एम3 की 16.4 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि वर्ष 2005-06 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण में अनुमानित 14.5 प्रतिशत से न केवल अधिक थी अपितु एक वर्ष पूर्व अवलोकित दर से भी अधिक थी। चालू वर्ष के दौरान मुद्रा आपूर्ति में द्रुत वृद्धि के बावजूद मूल्य स्थिरता, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के समुचित उदाहरण में विश्वास पर आधारित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं की स्थिरता तथा ऋण वृद्धि की निवेश प्रेरक प्रकृति को प्रमाणित करती है।

1.24 मुद्रा गुणक (प्रारक्षित मुद्रा एम₀ के प्रति एम₃ का अनुपात) मार्चांत 2004 में 4.59 से स्थिर रूप से बढ़कर मार्चांत 2005 में 4.61 हो गया तथा और बढ़ कर 20 जनवरी, 2006 को 4.77 पर पहुंच गया। यह प्रारक्षित-जमाराशि अनुपात में गिरावट को प्रतिबिम्बित करता है—उदाहरणार्थ 21 जनवरी, 2005 तथा 20 जनवरी 2006 के बीच 0.064 से 0.061। परिणामतः, प्रारक्षित मुद्रा (एम₀) में अभिवृद्धि एम₃ की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी सी धीमी थी। इसके अतिरिक्त, एम₀ की अभिवृद्धि मार्चांत 2004 में 18.3 प्रतिशत से ह्रासित होकर मार्चांत 2005 में 12.1 प्रतिशत हो गई। विगत वर्ष में अवलोकित ह्रास को जारी रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में 20 जनवरी, 2006 को एम₀ की अभिवृद्धि विगत वर्ष की सदृश तिथि को अवलोकित 15.3 प्रतिशत की तुलना में 14.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2004-05 में एम₀ के विकास में भारतीय रिज़र्व बैंक के एन एफ ए की अभिवृद्धि प्रबल थी।

1.25 वर्ष 2004-05 में, एनएफए में इस अभिवृद्धि के एक भाग को बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) तथा नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) का सहारा लेकर निष्फल करना पड़ा तथा परिणामतः भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) में गिरावट आई। भारतीय रिज़र्व बैंक के एनडीए की तुलना में एनएफए के सापेक्ष महत्व में वर्ष 2004-05 की तुलना में चालू वर्ष में अब तक तीव्र परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2004-05 में मार्चांत तथा 21/20 जनवरी के बीच हालांकि एनएफए में 75,930 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी, वर्ष 2005-06 में सदृश वृद्धि केवल 2,043 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2004-05 में, नकदी को समाहित करने तथा भुगतान संतुलन के माध्यम से प्रारक्षित अंतर्प्रवाहों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उनके व्यापक प्रयोग से, एमएसएस तथा एलएएफ (प्रतिवर्ती रिपो) के तहत बकाया अधिशेष 31 मार्च 2005 को 83,500 करोड़ रुपए (एम₃ का 3.7 प्रतिशत) था।

1.26 विदेशी मुद्रा के अर्थ में प्रारक्षित भंडारों में गिरावट से, मुद्रा के सांकेतिक मूल्यहास के बावजूद वर्ष 2005-06 में 20 जनवरी 2006 तक रुपया अर्थ में एनएफए प्रवाहों में कमी आई। दिसम्बर, 2005 के मध्य से नकदी की कमी के चिन्ह अवलोकित किए गए जो अंशतः 29 दिसम्बर 2005 को भारतीय स्टेट बैंक के भारत मिलेनियम डिपाज़िट (आईएमडी) के मोचन के कारण थे। आईएमडी मोचन के तहत कुल व्यय लगभग 32,000 करोड़ रुपए था तथा नकदी की कमी की प्रत्याशा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 दिसम्बर, 2005 को रिपो (एलएएफ) के तहत, 1,085 करोड़ रुपए सन्निविष्ट किए तथा इसके पश्चात् 27 दिसम्बर तथा 30 दिसम्बर, 2005 के बीच के चार दिनों में क्रमशः 21,415 करोड़ रुपए, 26,685 करोड़ रुपए, 30,110 करोड़ रुपए तथा 29,795 करोड़ रुपए की नकदी का और सन्निवेशन किया। 2 जनवरी, 2006 तथा 13 जनवरी 2006 के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिपो (एलएएफ) के तहत औसतन 16,527 करोड़ रुपए प्रति दिन का सन्निवेशन किया था। तथापि, वर्ष के दौरान एमएसएस तथा एलएएफ के माध्यम से समाहित नकदी के एक भाग को निर्मुक्त करने के परिणामस्वरूप उन के बकाया अधिशेष गिरकर 20 जनवरी, 2006 को 40,178 करोड़ रुपए (एम₃ का 1.6 प्रतिशत) हो गए।

1.27 मांग मुद्रा दरें ऊर्ध्वमुखी रूझान का अनुसरण करते हुए 30 अप्रैल 2005 को 4.94 प्रतिशत पर पहुंच गई जब नियत प्रतिवर्ती रिपो दर को 25 आधार बिंदु बढ़ाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया। तत्पश्चात् मांग मुद्रा दरें विशेषतया अक्टूबर, 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ती रिपो दर में 25 आधार बिंदु की वृद्धि के पश्चात् पुनः बढ़ना शुरू होने से पूर्व काफी समय तक लाभप्रद बनी रहीं। चालू वित्तीय वर्ष में पहली बार मांग मुद्रा दरें 9 नवम्बर, 2005 को 6 प्रतिशत को पारकर 6.10 प्रतिशत पर पहुंच गई तथा 11 नवम्बर, 2005 को और बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गई। 2-3 दिसम्बर, 2005 को नियत प्रतिवर्ती रिपो दर (5.25 प्रतिशत) से नीचे रहने के पश्चात्, अग्रिम कर भुगतानों तथा आगामी आईएमडी मोचन के दबावाधीन मांग दरें तीव्रता से बढ़नी शुरू होकर 29 दिसम्बर, 2005 की मोचन तिथि को 7.15 प्रतिशत पर पहुंच गई। तत्पश्चात्, दबावाधीन रहते हुए मांग दरें 27 जनवरी, 2006 को 7.71 प्रतिशत पर पहुंच गई किन्तु 16 फरवरी 2006 को संतुलित होकर 6.88 प्रतिशत हो गई।

1.28 वर्ष 2004-05 में, बढ़ती ब्याज दरों का बांड मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा बैंकों के राजकोष लाभ कम हो

गए। वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आय में वर्ष 2003-04 में अवलोकित 6.7 प्रतिशत की तुलना में 1.5 प्रतिशत (रूपांतरण से निवल) की अपेक्षाकृत मंद दर पर वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, जमाराशियों की तुलना में ऋण के तीव्रता से बढ़ने के कारण उधार लेने जैसे निधियन स्रोतों का वर्धित सहारा लिया जाने लगा। वर्ष 2004-05 में निवल आय के अनुपात के रूप में प्रचालनात्मक व्यय वर्ष 2003-04 में 45.4 प्रतिशत से बढ़कर 49.1 प्रतिशत हो गए; तथा कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में विगत वर्ष में 2.21 प्रतिशत से मामूली रूप से गिर कर 2.16 प्रतिशत हो गए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल ऋणों तथा अग्रिमों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ संयोजित एनपीए की वसूली में महत्वपूर्ण सुधार के परिणामस्वरूप सकल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए का अनुपात मार्चांत 2004 में 7.2 प्रतिशत से तीव्रता से गिरकर मार्चांत 2005 में 5.2 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का 12.8 प्रतिशत का समग्र अनुपात विगत वर्ष के स्तर (12.9 प्रतिशत) से मामूली रूप से कम था।

1.29 हाल के वर्षों में अवलोकित रूझान से सुस्पष्ट अपवर्तन करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में वृद्धि की गति में चालू वर्ष के दौरान अब तक तीव्र मंदी आई है। वर्ष 2004-05 के दौरान 28.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि के पश्चात्, चालू वर्ष में 10 फरवरी, 2006 तक मार्चांत 2005 में 141.5 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों के स्तर से 1.1 बिलियन अमरीकी डालर की कमी हुई है। इस प्रतिवर्तन के कारणस्वरूप तीन प्रमुख घटक हैं:— आईएमडी मोचन पर 7.1 बिलियन अमरीकी डालर का व्यय; अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में कमजोर हुए डालर से मूल्यांकन हानियां; तथा भुगतान संतुलन के वर्तमान खाते में बढ़ता घाटा।

1.30 अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर का कमजोर होना, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के प्रथमार्ध में प्रारक्षित भंडारों में 5.0 बिलियन अमरीकी डालर की मूल्यांकन हानियां हुई, अमरीकी डालर की तुलना में रूपए की घटबढ़ में भी प्रतिबिम्बित हुआ। वर्ष 2004-05 के दौरान, रूपए का मूल्य सांकेतिक अर्थों में अमरीकी डालर की तुलना में बढ़ गया (2.2 प्रतिशत) जबकि इसमें यूरो (-4.5 प्रतिशत), पाउंड (-6.3 प्रतिशत) तथा जापानी येन (-2.6 प्रतिशत) की तुलना में मूल्यहास हुआ। तथापि, वर्ष 2005-06 के प्रथम दस महीनों में, रूपए का मूल्य सभी

प्रमुख मुद्राओं की तुलना में औसतन बढ़ा है। यह मूल्यवृद्धि जापानी येन (6.4 प्रतिशत) की तुलना में सर्वाधिक थी जिसके पश्चात् क्रम में पाउंड (4.5 प्रतिशत) यूरो (4.3 प्रतिशत) तथा अमरीकी डालर (2.1 प्रतिशत) थे। वर्ष 2005-06 में, 5-देशीय निर्यात-भारित सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर) के अर्थों में (आधार वर्ष 2000) जुलाई, 2005 तक सभी महीनों में रूपए की मूल्य वृद्धि हुई तथा अनुवर्ती महीनों में दिसम्बर, 2005 तक इसमें मूल्यहास हुआ। 5-देशीय निर्यात-भारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) के अर्थों में (आधार वर्ष 2000), नवम्बर, 2005 को छोड़कर, जिसमें मामूली सी मूल्य वृद्धि परिलक्षित हुई, यही प्रतिमान अवलोकित किया गया।

1.31 भुगतान शेष के चालू खाते में प्रारम्भिक घाटे ने, जिसका आविर्भाव अधिशेष के तीन निरंतर वर्षों के पश्चात् वर्ष 2004-05 में हुआ, चालू वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत कही अधिक बड़े आयाम अभिग्रहीत किए। अप्रैल-सितम्बर, 2005-06 के दौरान, चालू खाता घाटा बढ़कर लगभग 13.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो वर्ष 2004-05 के सम्पूर्ण वर्ष में घाटे (5.4 बिलियन अमरीकी डालर) के दो गुणा से अधिक था। हालांकि निवल अदृश्यों में वृद्धि जारी रही, यह तीव्रता से विस्तारित होते व्यापार घाटे को प्रतिसंतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो अप्रैल-सितम्बर 2005-06 के दौरान 31.6 बिलियन अमरीकी डालर पर वर्ष 2004-05 के बारह महीनों में प्रलेखित घाटे से केवल लगभग 5.0 बिलियन डालर ही कम था।

1.32 चालू लेखा घाटे में तीव्र वृद्धि चालू वर्ष के दौरान अब तक के बढ़ते व्यापार घाटे को प्रतिबिम्बित करती है। निवल अदृश्यों में वृद्धि हुई किन्तु, यह बढ़ते व्यापार घाटे को प्रतिसंतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि वर्ष 2002-03 से पण्य निर्यातों में अवलोकित अभिवृद्धि जारी रही, इस अभिवृद्धि को पण्य आयातों में और भी अधिक तीव्र वृद्धि ने पीछे छोड़ दिया। पण्य आयातों में वर्ष 2003-04 से निर्यातों की अपेक्षा अधिक तीव्रतर वृद्धि हो रही है जो संभवतः उस समग्र औद्योगिक सुधार को प्रतिबिम्बित करती है जिसकी शुरुआत वर्ष 2002-03 की दूसरी तिमाही से हुई थी। सतत् कीमतों पर उपादान लागत पर सञ्चु की अभिवृद्धि वर्ष 2003-04 में 7.0 प्रतिशत को पार कर गई तथा तब से यह उस दर से अधिक ही रही है। पण्य आयातों की, वृद्धि में यह सतत् अभिवृद्धि संभवतया भारतीय उद्योग की वर्धनात्मक उत्पादकता तथा प्रभावशीलता से प्रत्युत्पन्न आयातों की भारी मांग के कारण हुई होगी।

1.33 भारत के पण्य निर्यात (अमरीकी डालर अर्थों में तथा सीमाशुल्क आधार पर) वर्ष 2002-03 से 20 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक अभिवृद्धि दरें दर्ज करते रहे हैं। वर्ष 2004-05 में, ऐसे निर्यातों में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि होकर ये 80 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गए जो विगत तीन दशकों में अब तक की सर्वाधिक उच्च वार्षिक अभिवृद्धि दर है। पाँच प्रमुख क्षेत्रों—रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरी वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद, अयस्क तथा खनिज, एवं रसायन और संबंधित उत्पाद इसके प्रमुख अभिप्रेरक थे। 18.9 प्रतिशत की कुछ कुछ अपेक्षाकृत निम्नतर अभिवृद्धि दर को दर्ज करते हुए, अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान निर्यात पहले ही 74.9 बिलियन डालर के स्तर पर पहुँच गए हैं तथा वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारित 92 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं।

1.34 वर्ष 2004-05 में पण्य आयात (अमरीकी डालर के संदर्भ में तथा सीमाशुल्क आधार पर) 39.7 प्रतिशत बढ़े थे जो अढ़ाई दशकों में सर्वोच्च अभिवृद्धि है। चालू वर्ष में मंदी के चलते अप्रैल-जनवरी, 2005-06 के दौरान ऐसे आयातों में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयात में वृद्धि अन्य बातों के अलावा कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तीव्र वृद्धि से प्रेरित थी जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल-जनवरी 2005-06 में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के आयात 46.9 प्रतिशत बढ़े। तेल-भिन्न, सर्राफा-भिन्न आयातों में अप्रैल-अक्टूबर, 2005 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 29.9 प्रतिशत के पश्चात् 30.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.35 वर्ष 2003-04 में 10.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 27.8 बिलियन अमरीकी डालर होने के पश्चात् निवल अदृश्यों में वृद्धि वर्ष 2004-05 में सिर्फ 3.4 बिलियन अमरीकी डालर पर सीमित थी जो मुख्यतया निजी अंतरणों में 1.4 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट के कारण थी। तथापि, निवल कारक-भिन्न सेवाओं द्वारा अभिग्रहित सेवा निर्यातों और जिनमें साफ्टवेयर व आई-टी-सक्षम सेवाएं शामिल थी, में निरंतर नियमित अनवरत संतोषजनक निष्पादन जारी है। ऐसे आयात (अमरीकी डालर के अर्थ में) वर्ष 2004-05 में 71.3 प्रतिशत बढ़ने के पश्चात् वर्ष 2005-06 के प्रथमार्द्ध में 75.3 प्रतिशत और बढ़ गए। साफ्टवेयर और आई-टी-सक्षम सेवाओं के अतिरिक्त काफी समय से व्यावसायिक सेवाओं सहित व्यापार सेवाएं हाल के वर्षों में सेवाओं के निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं।

1.36 वर्ष 2004-05 के दौरान सुदृढ़ अंतर्प्रवाहों के साथ पूंजी खाते में दर्ज किए गए 31.6 बिलियन अमरीकी डालर

के अधिशेष से चालू खाता घाटे की अपेक्षा अधिक की क्षतिपूर्ति हुई तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार के वर्तमान स्टाक में बी.ओ.पी. आधार पर 26 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। अप्रैल-सितम्बर 2005 में, जबकि 19.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पूंजी खाता अधिशेष 13.0 बिलियन अमरीकी डालर के चालू खाता घाटे की तुलना में अधिक रहा, बी.ओ.पी. आधार पर प्रारक्षित भंडार अभिवृद्धि में मंदी आयी। पूंजी खाते में ऋण-भिन्न सृजनकारी अंतर्प्रवाहों का वर्चस्व बना रहा। अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान 7.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वर्ष 2004-05 के पूर्वार्ध के 2.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऐसे अंतर्प्रवाहों की तुलना में लगभग 5.0 बिलियन अमरीकी डालर अधिक थे। विदेशी निवेश के अंतर्गत, पोर्टफोलियो प्रवाह, जिनमें मुख्य हिस्सा विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) निवेश का है, प्रबल किस्म के थे। अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान 4.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर विदेशी संस्थागत निवेशक प्रवाह (निवल) न केवल 2.3 बिलियन अमरीकी डालर के एफ.डी.आई प्रवाहों की तुलना में, बल्कि अप्रैल-सितम्बर, 2004 के 339 मिलियन अमरीकी डालर के एफ.आई.आई. प्रवाहों की तुलना में भी अधिक थे। अप्रैल-सितम्बर 2005 के दौरान एफडीआई प्रवाह (निवल) 2.3 बिलियन अमरीकी डालर के थे जो वर्ष 2004-05 के प्रथमार्ध में 2.0 बिलियन अमरीकी डालर के ऐसे प्रवाहों से केवल 0.3 बिलियन अमरीकी डालर ही अधिक थे।

1.37 पूंजीगत लेखा में ऋण-भिन्न सृजनकारी प्रवाहों का वर्चस्व होते हुए भी वर्ष 2004-05 से चालू खाता घाटा के अविर्भाव से ऋण प्रवाहों का महत्व बढ़ गया प्रतीत होता है। विदेशी सहायता और विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) दोनों, जो वर्ष 2002-03 और वर्ष 2003-04 के दौरान निवल बहिर्प्रवाह थे, वर्ष 2004-05 के दौरान क्रमशः 1.9 बिलियन अमरीकी डालर तथा 5.0 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अंतर्प्रवाह हो गए। चालू वर्ष के प्रथमार्ध में ये प्रवाह धनात्मक बने रहे। विशेषतया ईसीबी वर्ष 2004-05 के प्रथमार्ध और वर्ष 2005-06 के प्रथमार्ध के बीच 1.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। अनिवासी जमाराशियां भी, जो ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दर प्रीमियमों के यौक्तिकीकरण के पश्चात् बहिर्प्रवाहों में परिवर्तित हो गई थीं, चालू वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान निवल अंतर्प्रवाहों में परिवर्तित हो गयीं। सितम्बर, 2005 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण जो 124.3 बिलियन अमरीकी डालर था, मार्चांत 2005 के स्तर से 1.0 बिलियन अमरीकी डालर अधिक था।

यह वृद्धि मुख्यतः अल्पावधिक विदेशी ऋण जैसे ईसीबी और आयातकों द्वारा लिए गए व्यापार ऋण में वृद्धि होने के कारण थी। आईएमडी के मोचन से समग्र विदेशी ऋण में प्रत्याशित संतुलन को दिसम्बर, 2005 के लिए संकलित किए जा रहे आंकड़ों में शामिल किया जाएगा।

1.38 अवसंरचनात्मक अपर्याप्तताएं औद्योगिक पुनरूत्थान, निवेश में तेजी और उत्प्लावक निर्यातों की पूर्ण क्षमता में बाधक बनी रहीं। उदाहरण के लिए अप्रैल-दिसम्बर, 2005 में विद्युत उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि न केवल वार्षिक लक्ष्य से कम थी अपितु विगत वर्ष की इसी अवधि में हासिल की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से भी कम थी। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में छह महत्वपूर्ण उद्योगों-कोयला, विद्युत, कच्चा पेट्रोलियम, शोधनशाला उत्पादन, इस्पात और सीमेंट जिनका अवसंरचना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, के समग्र सूचकांक में 4.5 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की गई जो अप्रैल-दिसम्बर 2004 के दौरान दर्ज की गई 6.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी। वर्ष 2005-06 के प्रथमार्ध में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई और कोयला, विद्युत तथा इस्पात के क्षेत्रों में अभिवृद्धि में कमी हुई। तथापि, इस अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन की अभिवृद्धि में तेजी आई।

1.39 यद्यपि दूरसंचार, पत्तनों और हवाई पत्तनों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने में प्रगति जारी रही, मोटर स्पिरिट तथा उच्च गति डीजल पर वर्धित सड़क उपकरण के माध्यम से वित्तपोषित सड़कों के बजटीय परिव्ययों में अभिवृद्धि हुई। तथापि, अवसंरचना में कुल निवेश आवश्यकता से काफी कम रहा, और उदाहरणार्थ विद्युत, गैस और जलपूर्ति के निवल पूंजी भण्डार में वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 2003-04 के बीच 3.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से अभिवृद्धि हुई। हाल ही में शुरू की गई सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को विद्युत तथा खनन के क्षेत्र में सीमित सफलता मिली और सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व जारी रहा।

1.40 निवेश में आई तेजी, हालिया विगत में विशेषतया वर्ष 2003-04 से, जिसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एआरबीएमए), अधिनियमित किया गया था, राजकोषीय समेकन में हुई प्रगति को आंशिक रूप से दर्शाती है। सरकार द्वारा क्रेडिट के पूर्वक्रय में कटौती किए जाने से सौम्य ब्याज दर की व्यवस्था बनाए रखने और पूंजी निर्माण को प्रेरित करने में सहायता मिली। एफआरबीएमए के तहत नियमों में राजकोषीय घाटे में संघर्ष के 0.3 प्रतिशत और राजस्व घाटे में संघर्ष के 0.5 प्रतिशत की वार्षिक

न्यूनतम कटौती करना अधिदेशित है। वर्ष 2003-04 से बाद के दो वर्षों में राजकोषीय सुस्वस्थता के दो संकेतकों में से प्रत्येक में संघर्ष की 0.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत कमी की गई है। हासिल किए गए इस द्रुत राजकोषीय समायोजन ने उल्लेखनीय रूप से नब्बे के दशक के मध्य की पूर्व यथास्थिति को बहाल कर दिया। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के अधिनिर्णय को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के बजट में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। तथापि, 2005-06 के लिए संशोधित अनुमानों के पता चलने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आयेगी।

1.41 ऐसे संकेत मिलते हैं कि चालू वर्ष में केन्द्र में राजकोषीय समेकन में हुई अपेक्षाकृत धीमी प्रगति को राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत तीव्र प्रगति करके क्षतिपूरित किया जाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप सामान्य सरकार अर्थात् केन्द्र और राज्यों की संयुक्त वित्तीय सुस्वस्थता में समग्र सुधार होगा। 2 फरवरी, 2006 तक 18 राज्यों में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान लागू कर दिए थे और कई और राज्यों ने इन्हें अपनाए की कार्यवाही शुरू कर दी थी। पहली अप्रैल, 2005 से अधिकांश राज्यों ने वैट, जो एक गैर-प्रपाती, स्वप्रवर्तनकारी और सुमेलित वस्तु कराधान व्यवस्था है, को अपना लिया था। राज्यों में उत्प्लावक राजस्व और वर्ष 2004-05 (संअ०) में राज्यों की संयुक्त राजकोषीय स्थिति में हुए महत्वपूर्ण सुधार यह निर्दिष्ट करते हैं कि टीएफसी द्वारा यथा परिकल्पित राजकोषीय सुधारों को प्रखर बनाने और सार्वजनिक वित्त व्यवस्था की पुनर्संरचना का कार्य आरम्भ हो गया है। वर्ष 2004-05 (संअ०) में राज्यों का राजस्व घाटा कम होकर संघर्ष का 1.4 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा संघर्ष का 3.8 प्रतिशत हो गया। बजट अनुमान 2005-06 में इसे अग्रणीत करके राजस्व घाटे के लिए संघर्ष के 0.7 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के लिए संघर्ष के 3.1 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया। ये टीएफसी द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्य के बहुत करीब थे और अधिनिर्णय के प्रथम वर्ष में ही इनकी प्राप्ति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की द्योतक है।

1.42 वर्ष 1998-99 को छोड़कर, वर्ष 1990-91 से अपनी अभिवृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखने से केन्द्रीय कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वर्ष 1990-91 में 19.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 (संअ०) में 43.3 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2005-06 (ब०अ०) में और बढ़कर 47.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में दरों में कटौती

करने, व्यापकाधार और बेहतर अनुपालन के जरिए राजस्व जुटाने की प्रक्रिया को जारी रखा गया है। वैयक्तिक आयकर में एक समान महत्वपूर्ण कटौती और मूल निगम आयकर में 5 प्रतिशतांक की कटौती इसके संकेतक हैं। कृषि-भिन्न मदों पर सीमा शुल्क की चरम दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल पर सीमा शुल्क कम किया गया और भारतीय उपभोक्ताओं पर पेट्रोलियम की बढ़ती वैश्विक कीमतों के प्रभावी प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्कों के भागों को यथामूल्य से विशिष्ट में परिवर्तित किया गया। वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में की गई एक प्रमुख घोषणा राज्य उदग्रहणों की विसंगतिपूर्ण स्थिति में आंशिक सुधार करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा परिकल्पित समर्थकारी प्रावधान था जो केवल घरेलू उत्पादों पर प्रयोज्य है और अंत प्रयोक्ताओं द्वारा आयातों पर नहीं। यह अतिरिक्त सीमाशुल्क 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

उपभोग, बचतें और निवेश

1.43 राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला के अनुसार सञ्चय के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतों में अभिवृद्धि की वर्ष 2001-02 से अवलोकित प्रवृत्ति जारी रही, जिसमें बचत का अनुपात वर्ष 2002-03 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 28.9 प्रतिशत और वर्ष 2004-05 में और बढ़कर 29.1 प्रतिशत हो गया (सारणी 1.3)। वर्ष 2004-05 में, बचत दर में वृद्धि इसके तीन घटकों में से दो घटकों अर्थात् सार्वजनिक और कारपोरेट बचतों के कारण हुई। तृतीय घटक अर्थात् घरेलू बचतें 5.9 प्रतिशत की दर से वर्धित हुई यह वृद्धि सञ्चय की अभिवृद्धि दर से कम थी और सञ्चय के अनुपात के रूप में कम होने के कारण इसका योगदान ऋणात्मक था।

1.44 सार्वजनिक बचतों में प्रवृत्ति ऋणात्मक (वर्ष 1998-99 से वर्ष 2002-03) से प्रतिवर्तित होकर वर्ष 2003-04 में धनात्मक हो गई। एफआरबीएमए के क्रियान्वयन में प्रगति होने के साथ यह लाभकारी प्रवृत्ति और अधिक

सारणी 1.3 : बचत और निवेश

(नई श्रृंखला आधार 1999-2000)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (पी)	2004-05 (क्यू)
(वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)						
सकल घरेलू बचतें	24.9	23.5	23.6	26.5	28.9	29.1
क) सरकारी	-0.9	-1.8	-2.0	-0.7	1.0	2.2
ख) निजी	25.7	25.3	25.6	27.2	27.9	26.8
i) पारिवारिक	21.3	21.2	22.0	23.1	23.5	22.0
वित्तीय	10.5	10.2	10.8	10.3	11.5	10.3
वास्तविक	10.7	11.0	11.2	12.7	12.0	11.7
ii) निजी कारपोरेट	4.5	4.1	3.6	4.1	4.4	4.8
सकल घरेलू निवेश*	26.0	24.2	23.0	25.3	27.2	30.1
सरकारी	7.5	6.9	6.9	6.2	6.5	7.2
निजी	17.9	16.7	16.8	18.5	18.9	20.0
बहुमूल्य वस्तुएं	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3
जीएफसीएफ	23.3	22.7	23.1	24.1	24.7	25.9
स्टॉक में परिवर्तन	2.0	0.9	0.6	0.6	0.7	1.4
भूल-चूक	-0.1	-0.1	-1.3	0.1	1.0	1.6
बचत-निवेश में अंतर@	-1.1	-0.6	0.6	1.2	1.6	-1.0
सरकारी	-8.3	-8.7	-8.9	-6.8	-5.5	-5.0
निजी	7.8	8.6	8.8	8.6	9.0	6.9

टिप्पणी : (i) सकल घरेलू निवेश सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) का द्योतक है।
(ii) आंकड़े पूर्णक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं।

* : भूल-चूक के लिए समायोजित

@ : बचत और निवेश की दरों के बीच अंतर का द्योतक है।

जी.एफ.सी.एफ. : सकल नियत पूंजी निर्माण

पी : अनन्तिम क्यू : त्वरित अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

सुदृढ़ हो गई जब सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें वर्ष 2003-04 में संघण्ड के 1.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में संघण्ड का 2.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2004-05 (त्वणण) में 69,390 करोड़ रुपए की धनात्मक बचत में सार्वजनिक प्राधिकरणों के निम्नतर अधिव्यय और गैर विभागीय उद्यमों की उच्चतर बचतें शामिल हैं।

1.45 निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा की गई बचतें जो उनके उच्चतर मुनाफों से उच्च प्रतिधारित अर्जन को प्रतिबिम्बित करती हैं, तीव्रता से बढ़ीं (24.9 प्रतिशत) जिससे संघण्ड में इनका हिस्सा वर्ष 2003-04 में 4.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 (त्वणण) में 4.8 प्रतिशत हो गया। तीन वर्षों तक निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचतों में उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति का संवेग जारी रहा; संघण्ड के अनुपात के रूप में यह वर्ष 2001-02 में 3.6 प्रतिशत से सुस्थिर रूप से बढ़ती हुई वर्ष 2004-05 (त्वणण) में संघण्ड का 4.8 प्रतिशत हो गयीं। सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष, वित्तीय और वास्तविक परिसम्पत्तियों, दोनों में, घरेलू बचतों में गिरावट के कारण वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के बीच सकल घरेलू बचत दर में 0.2 प्रतिशतांक की वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष में 2.4 प्रतिशतांक की वृद्धि की अपेक्षा काफी कम थी।

1.46 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में वर्तमान कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वर्ष 1999-2000 में 64.6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2002-03 में 62.9 प्रतिशत हो गया, फिर यह और गिरकर वर्ष 2003-04 में 62.4 प्रतिशत और वर्ष 2004-05 में 60.6 प्रतिशत हो गया। पीएफसीई के विभिन्न संघटकों के बीच, कुल व्यय में खाद्य, पेय पदार्थों और तम्बाकू का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 46.8 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2004-05 में 40.6 प्रतिशत हो गया। पीएफसीई के अनुपात के रूप में अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण मदों जैसे परिवहन और संचार में वर्ष 2000-01 में वृद्धि 14.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 18.2 प्रतिशत हो गई।

1.47 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मापे जाने पर जहां उपभोग व्यय में सरकारी और निजी दोनों उपभोग श्रेणियों में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, राष्ट्रीय आय के मांग पक्ष में इस व्यय का प्रभुत्व जारी रहा। चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सरकारी अन्तिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) वर्ष 1999-2000 में 12.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2003-04 में 11.2 प्रतिशत हो गया। इस अनुपात के वर्ष 2004-05 में मामूली रूप से बढ़कर 11.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

1.48 वर्ष 2002-03 और वर्ष 2003-04 में सकल घरेलू बचतों की दर में वृद्धि के समनुरूप पर जीडीसीएफ या निवेश की दर में वृद्धि हुई (सारणी 1.3)। तथापि, जीडीसीएफ में वृद्धि बचतों में वृद्धि की अपेक्षा कम थी, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में क्रमशः 1.2 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत का भुगतान संतुलन में चालू खाता अधिशेष रहा। वर्ष 2004-05 में अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि को प्रतिबिम्बित करते हुए, जीडीसीएफ में सकल घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सकल घरेलू बचतों के अनुपात में 0.2 प्रतिशतांक वृद्धि से अधिक है। भुगतान संतुलन में संघण्ड के 0.8 प्रतिशत के चालू खाता घाटे ने काफी हद तक बचत-निवेश अन्तर को पाट दिया।

1.49 सकल घरेलू निवेश वर्ष 2003-04 में 27.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 30.1 प्रतिशत हो गया (सारणी 1.3) जो मुख्यतया निजी निवेश में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण था। संशोधित श्रृंखला आंकड़ों में, संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा-विवरणों की 1993 प्रणाली के आधार पर, एक नई मद "बहुमूल्य वस्तुएं" को शामिल किया गया है, जिसमें मूल्य के भंडार के रूप में बहुमूल्य धातुओं एवं पत्थरों की अधिप्राप्ति संबंधी व्यय को सरकारी और निजी से पृथक, जीडीसीएफ के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

1.50 सतत् कीमतों (आधार वर्ष 1999-2000) पर जीडीसीएफ, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में निरन्तर रूप से चालू मूल्यों पर तदनुसूची अनुपात से कम है (सारणी 1.3)। परन्तु भारांशों के रूप में सतत् या चालू मूल्यों का चुनाव कुछ भी हो, वर्ष दर वर्ष परिवर्तन की दिशा अपरिवर्तित रहती है। सामान्य रूप में अर्थव्यवस्था में और विशेषरूप से विनिर्माण में उत्पादन प्रक्रियाओं के बढ़ते हुए प्रौद्योगिकीय अत्याधुनिकीकरण से सतत् कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में जीडीसीएफ में परिवर्तन के न्यूनतर मूल्य सामान्य मूल्य स्तर के सापेक्ष पूंजीगत वस्तुओं के उच्चतर मूल्यों को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं।

1.51 सतत् 1999-2000 कीमतों पर, वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के लिए जीडीसीएफ की संरचना निजी की अपेक्षा सार्वजनिक संघटक में तीव्रतर वृद्धि दर्शाती है। इसके अतिरिक्त पिछले दो वर्षों में वस्तु सूचियों और बहुमूल्य वस्तुओं में तीव्रतर वृद्धि हुई है, जिसमें सकल नियत पूंजी निर्माण में (जीएफसीएफ) सकल घरेलू पूंजी निर्माण की

सारणी 1.4 : वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण						
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (पी)	2004-05 (क्यू)
(बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 1999-2000 मूल्य)						
जी.डी.सी.एफ. *	26.0	23.9	22.3	25.0	26.7	28.5
सरकारी	7.5	6.9	6.8	6.1	6.3	6.8
निजी	17.9	16.4	16.2	18.2	18.6	18.9
निजी कापॉरिट क्षेत्र	7.2	5.6	5.4	5.7	6.9	8.2
पारिवारिक क्षेत्र	10.7	10.8	10.8	12.5	11.7	10.7
बहुमूल्य वस्तुएं	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3
जी.एफ.सी.एफ.	23.3	22.4	22.4	23.7	24.4	24.6
सरकारी	6.6	6.4	6.3	6.3	6.6	6.6
निजी	16.7	16.0	16.0	17.5	17.8	18.0
स्टॉक में परिवर्तन	2.0	0.9	0.5	0.6	0.5	1.1
सरकारी	0.9	0.5	0.4	-0.1	-0.2	0.2
निजी	1.1	0.4	0.1	0.7	0.7	0.8
(वृद्धि दर प्रतिशत में)						
जी.डी.सी.एफ.*		-4.5	-1.9	16.5	15.8	15.7
सरकारी		-4.0	3.2	-6.0	11.8	16.7
निजी		-4.6	3.8	16.9	10.3	10.4
जी.एफ.सी.एफ.		0.0	5.0	9.9	11.3	9.5
सरकारी		1.3	3.9	2.2	13.7	8.6
निजी		-0.6	5.5	13.0	10.5	9.8
टिप्पणी : जीडीसीएफ : सकल घरेलू पूंजी निर्माण; जीएफसीएफ : सकल नियत पूंजी निर्माण; आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं। * : भूल-चूक के लिए समायोजित पी : अनन्तम; क्यू : त्वरित अनुमान स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन						

अपेक्षा न्यूनतर दर से वृद्धि हुई है। यह आंशिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में स्टॉकों में परिवर्तन में वर्ष 1999-2000 में 2.0 प्रतिशत से वर्ष 2001-02 में 0.5 प्रतिशत की तीव्र गिरावट की समायोजन की प्रक्रिया और स्वर्ण व चांदी के आयातों के प्रगामी उदारीकरण को प्रतिबिम्बित करता है।

1.52 मांग पक्ष से, चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में अंशदान के संदर्भ में पीएफसीई के पैटर्न में परिवर्तन आया जो अग्रणी रहा (चित्र 1.2 और सारणी 1.5)। पीएफसीई ने वर्ष 2000-01 और वर्ष 2003-04 के बीच चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 54.5 प्रतिशत का उच्च अंशदान किया। निजी अंतिम उपभोग व्यय का प्रतिशतांक अंशदान वर्ष 2003-04 में सञ्चु में 12.7 प्रतिशत की समग्र वृद्धि में से 7.4 प्रतिशत पर उच्च था। उसी वर्ष, निवेश का तदनुसूची अंशदान 5.4 प्रतिशत था। एक उत्साहवर्धक घटनाक्रम में, वर्ष 2004-05 में सञ्चु में निवेश का 13.1 प्रतिशत वृद्धि में से 6.8 का प्रतिशतांक अंशदान

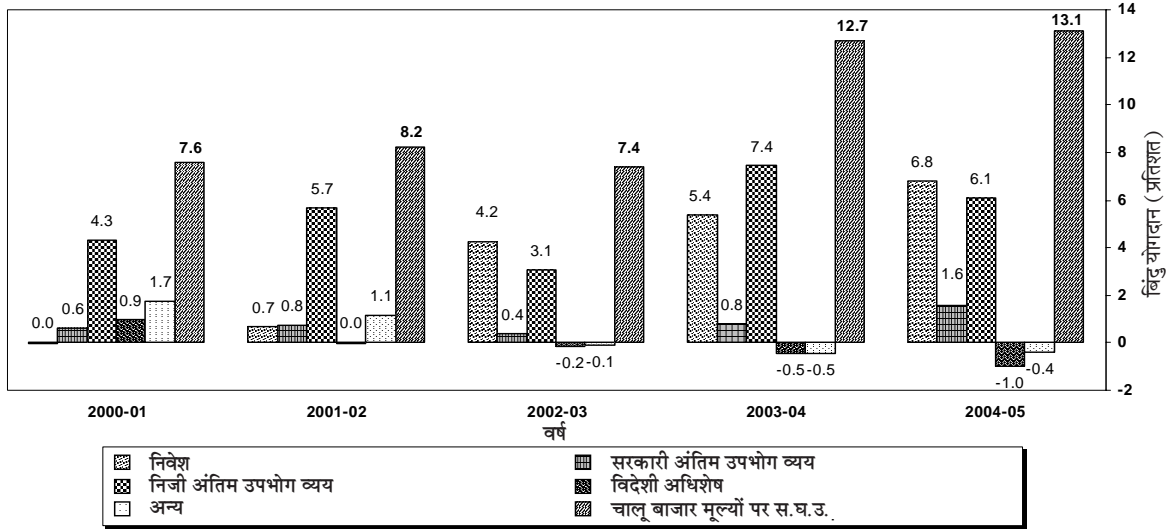
हाल के वर्षों में पहली बार 6.1 के निजी अंतिम उपभोग व्यय के तदनुसूची अंशदान से अधिक था। निर्यातों के सापेक्ष आयातों की उच्चतर वृद्धि को प्रतिबिम्बित करते हुए, वैदेशिक शेष का ऋणात्मक अंशदान वर्ष 2004-05 में बढ़ गया।

उत्पादन

1.53 चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2003-04 में 213.5 मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2004-05 में 204.6 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। 19 सितम्बर, 2005 को जारी वर्ष 2005-06 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों में खरीफ उत्पादन 105.3 मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष के स्तर से लगभग 2 मीट्रिक टन अधिक है। रबी की बुआई पूरी हो गई है और मौसम के अनुकूल रहने पर, रबी के उत्पादन के 101.2 मीट्रिक टन पर बने रहने की आशा है जो वर्ष 2004-05 के रबी उत्पादन जितना ही है। तथापि, फरवरी 2006 में उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में

चित्र 1.2

चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. वृद्धि में बिंदु योगदान



2.3 प्रतिशत की वृद्धि होकर इसके वर्ष 2004-05 में 204.6 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 209.3 मीट्रिक टन होने की आशा है। वर्ष 2004-05 में सूखे के प्रभाव से, विशेषरूप से मोटे अनाजों की पैदावार में गिरावट से, वर्ष 2003-04 की रिकार्ड पैदावार में सुधार अपूर्ण है। वर्ष 2003-04 से मोटे अनाजों की खरीफ पैदावार में गिरावट चालू वर्ष में जारी रहने की आशा है। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2005-06 के लिए खरीफ तिलहनों का

उत्पादन 14.6 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अनुकूल मौसम होने पर रबी तिलहनों का उत्पादन 10.4 मीट्रिक टन के लक्ष्य स्तर तक पहुंच सकता है। वर्ष 2005-06 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों में गन्ना उत्पादन 257.7 मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2004-05 में 232.3 मीट्रिक टन से बहुत अधिक प्रतिवर्तन है। तथापि, वर्ष 2005-06 में कपास, जूट और मेस्टा के उत्पादन की संभावनाएं वर्ष 2004-05 से बेहतर नहीं समझी गयी हैं।

सारणी 1.5 : सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का संघटन

संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन									
	(वर्तमान मूल्यों पर)					(1999-2000 मूल्यों पर)				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04पी	2004-05क्यू	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04पी	2004-05क्यू
कुल अंतिम उपभोग व्यय	6.3	8.4	4.5	11.0	10.4	1.9	5.2	1.2	7.0	6.7
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	4.8	6.0	3.0	6.6	14.2	0.3	1.7	-0.6	2.4	9.2
निजी अंतिम उपभोग व्यय	6.7	8.9	4.7	11.8	9.8	2.3	5.9	1.6	7.9	6.3
सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसमें से	-0.1	2.9	18.5	21.2	24.9	-4.5	-1.9	16.5	15.8	15.7
सकल नियत पूंजी निर्माण	4.7	10.2	11.8	15.7	18.3	0.0	5.0	9.9	11.3	9.5
वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	22.1	4.5	22.3	14.7	45.1	—	—	—	—	—
घटाइए - वस्तुओं और सेवाओं का आयात	12.0	4.5	22.2	16.7	47.7	—	—	—	—	—
बाजार मूल्यों पर स.घ.उ.	7.6	8.2	7.4	12.7	13.1	4.0	5.3	3.6	8.3	8.5

क्यू : त्वरित अनुमान। पी : अनन्तिम
 स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

1.54 वर्ष 2003-04 की दूसरी तिमाही से अवलोकित औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी बनी हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान वृद्धि वर्ष 2004 की इसी अवधि में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.8 प्रतिशत थी। तथापि, वर्ष 2005-06 की पहली छमाही में, संचयी आधार (उदाहरणार्थ अप्रैल-मई, अप्रैल-जून आदि) पर, आई आई पी वृद्धि वर्ष 2004-05 में तदनुसूची वृद्धि से अधिक थी। तथापि, उत्कृष्ट निष्पादन की यह प्रवृत्ति अक्टूबर 2005 से प्रतिवर्तित हो गई और वर्ष 2005-06 के पहले नौ महीनों के लिए आई आई पी वृद्धि वर्ष 2004-05 की इसी अवधि से कम हो गई।

1.55 चालू वर्ष की विशेषता विनिर्माण, जो उद्योग के तीन उप-क्षेत्रों में से एक है, में जबर्दस्त वृद्धि रही है। पहले नौ महीनों में से तीन में (मई, जून और अक्टूबर, 2005 जिसमें जून 2005 में 13.2 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई) वर्षानुवर्ष वृद्धि दो अंकों में थी। तथापि, उद्योग के भीतर खनन और विद्युत के अन्य दो-उप-क्षेत्रों का निष्पादन वर्ष 2004-05 की तुलना में बदतर था। खनन और विद्युत क्षेत्र के इस निराशाजनक निष्पादन ने औद्योगिक क्षेत्रक के समग्र निष्पादन को नीचे ला दिया।

1.56 विनिर्माण के भीतर, पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष अप्रैल-दिसम्बर 2005 में 15.7 प्रतिशत पर पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक की तीव्रतर वृद्धि ने अर्थव्यवस्था में निवेश के अत्यधिक प्रवाह के संबंध में मजबूत पुष्टिकारक साक्ष्य प्रदान किया। पूंजीगत वस्तुओं से केवल दूसरे स्थान पर, उद्योगों के प्रयोक्ता-आधारित वर्गीकरण में, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में 13.6 प्रतिशत की तीव्रतर वृद्धि हुई। वर्ष 2003-04 से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में निरन्तर तीव्र वृद्धि बैंकिंग सेक्टर में खुदरा उपभोक्ता ऋण के तीव्र विस्तार के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करती है। उपभोक्ता वस्तुओं में, टिकाऊ और गैर-टिकाऊ दोनों खंडों में गत दो वर्षों में द्विअंकीय अभिवृद्धि सहित बेहतर निष्पादन दर्ज किया गया है।

1.57 अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान द्विअंकीय स्तर पर 17 उद्योगों का निष्पादन विनिर्माण के अंतर्गत अभिवृद्धि की एक उचित व्यापकधारित पद्धति को रेखांकित करता है। सात उद्योगों में, जिनका आई.आई.पी. में कुल भार लगभग 34 प्रतिशत है, 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

वस्त्र उत्पादों (18.6 प्रतिशत) मादक पेय (16.4 प्रतिशत) और बुनियादी धातु (15.0 प्रतिशत) में अत्यंत प्रभावशाली निष्पादन हुआ है। पांच उद्योगों में, जिनका आई.आई.पी. में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान है, चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान ऋणात्मक वृद्धि देखी गई जिनमें से लकड़ी उत्पादों, धात्विक उत्पादों, चमड़ा उत्पादों और खाद्य उत्पादों में गिरावट तीव्रतर थी।

1.58 व्यष्टि उद्योगों में, ऑटोमोबाइल्स का सभी खंडों में उत्पादक वृद्धि के साथ विस्तार होना जारी रहा। भारतीय वाहन, विशेषकर, यात्री कारों और तिपहिया वाहन विदेशी बाजारों में महत्वपूर्ण प्रवेश मार्ग बना रहे हैं, ऐसी श्रेणियों से निर्यात वर्तमान उत्पादन स्तरों का 18-19 प्रतिशत बैठते हैं। वर्ष 1950-51 में 8,000 की तुलना में यात्री कारों के उत्पादन द्वारा चालू वर्ष में, एक मिलियन के चिह्न को पार कर जाने की आशा है। हालांकि सूती वस्त्र के उत्पादन, में अप्रैल-दिसम्बर, 2005 में 10.2 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है, अन्य मुख्य वस्त्रों जो ऊन, रेशम और मानव निर्मित रेशों से निर्मित हैं, में गिरावट आयी है। बने-बनाए वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात, दोनों की अभिवृद्धि में तेजी आई है जिन्हें 28 मार्च, 2005 से लघु-प्रारक्षण की परिधि से हटा लिया गया था।

1.59 अर्थव्यवस्था में संरचना गतिविधि में पुनरुत्थान द्वारा उत्प्लावित सीमेंट में अप्रैल-दिसम्बर, 2005 में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सदृश विगत अवधि में हुई 6.9 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। इस्पात उत्पादन, जिसमें तीन वर्षों से वृद्धि हो रही है, में अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो सदृश विगत अवधि में दर्ज की गई 7.5 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ी सी कम थी; परंतु विगत वर्ष की अंतिम तिमाही में निम्नाधार के कारण चालू वर्ष की अंतिम तिमाही में इसमें सुधार होने की आशा है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में ऊर्जा उत्पादों, विशेषकर पेट्रोलियम खंड में, कुछ कमियां दर्ज की गईं। अप्रत्याशित आपूर्ति प्रघातों के कारण चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आयी है; जब कि अप्रैल-दिसम्बर, 2004-05 में 7.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2005-06 में कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि भी घट कर 5.7 प्रतिशत रह गई है। कोयले की आपूर्ति में हुई गिरावट से तापीय विद्युत के खण्ड में वृद्धि में कमी आने से बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ।

मानव विकास, निर्धनता और बेरोज़गारी

1.60 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास रिपोर्टों के अनुसार—मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) का मूल्य—जो आय, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक संयुक्त संकेतक है, पिछले कुछ वर्षों में निरन्तर बढ़ा है। लेकिन, इस सूचकांक पर भारत का सापेक्ष वैश्विक दर्जा लगातार तीन वर्षों से 177 देशों की सूची में 127 वें स्थान पर काफी नीचे बना हुआ है। आय में हुई तीव्र वृद्धि के बावजूद यह असन्तोषजनक सापेक्ष प्रगति शिक्षा और स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार किए जाने की ज़रूरत को रेखांकित करती रही है।

1.61 हालांकि हाल की अवधियों के संबंध में आंकड़ों की उपलब्धता शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में समस्या बनी हुई है, फिर भी इन दोनों मोर्चों पर प्रगति, भले ही वह कुछ धीमी हो, के कुछ संकेत अवश्य हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 1991-95 से वर्ष 2001-06 के बीच, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 59.7 वर्ष से बढ़कर 63.9 वर्ष हो गई है और महिलाओं के लिए 60.9 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है। इसी प्रकार, शिक्षा में, सकल नामांकन अनुपात—प्रारंभिक स्कूलों में वास्तव में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के नामांकित बच्चों का अनुपात—1950-51 में 32.1 से क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ वर्ष 2001-02 में 82.4 हो जाने तथा इसके और बढ़कर वर्ष 2003-04 में 84.9 हो जाने का अनुमान लगाया गया है। अक्टूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2001 के 320 लाख से कम होती हुई 95 लाख हो गई थी।

1.62 निर्धनता के नवीनतम उपलब्ध आधिकारिक अनुमान वर्ष 1999-2000 से संबंधित हैं जब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में बड़े पैमाने पर पंचवार्षिक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 55वां दौर आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण में निर्धनता का विस्तार वर्ष 1993-94 के 36.0 प्रतिशत के स्तर से गिरकर वर्ष 1999-2000 में 26.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 1999-2000 में आंकड़ों के संग्रहण के तरीके में परिवर्तन के कारण वास्तविक गिरावट की तुलनीयता और विस्तार विवाद का विषय बन गई थी। हालांकि वर्ष 2004-05 के दौरान एनएसएसओ द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षण के 61वें दौर के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है, फिर भी वर्ष 1999-2000 से आगे की अवधि के लिए उपलब्ध वार्षिक सूक्ष्म-प्रतिदर्श सर्वेक्षण निर्धनता के विस्तार में निरन्तर

हो रही गिरावट का संकेत देते हैं। 61वें दौर के परिणाम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि निर्धनता विस्तार में हो रही गिरावट की दर दसवीं योजना में वर्ष 2007 तक निर्धनता को कम करके 19.3 प्रतिशत तक लाने के लिए ज़रूरी प्रवृत्ति के अनुरूप है या नहीं।

1.63 रोज़गार और बेरोज़गारी की स्थिति के संबंध में जनवरी-जून 2004 के दौरान आयोजित एनएसएसओ सर्वेक्षण के 60वें दौर के परिणाम अब उपलब्ध हैं। प्रतिदर्श का आकार, जो पिछले एनएसएसओ दौर के मानकों के अनुसार न तो बड़ा है और न ही छोटा, प्रतिदर्श संबंधी चूकों और साक्ष्य की निश्चितता के बारे में प्रश्न खड़े करने की गुंजाइश अवश्य छोड़ देता है। फिर भी, 60वें दौर में वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर बेरोज़गारी की दर, वर्ष 2004 में, पुरुषों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 9.0 प्रतिशत (वर्ष 1993-94 में 5.6 प्रतिशत से बढ़ते हुए) और शहरी क्षेत्रों में 8.1 प्रतिशत (वर्ष 1993-94 में 6.7 प्रतिशत से बढ़ते हुए) के स्तर पर थी। महिलाओं के लिए तदनुसूची आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में 9.3 प्रतिशत (5.6 प्रतिशत से बढ़ते हुए) और शहरी क्षेत्रों में 11.7 प्रतिशत (10.5 प्रतिशत से बढ़ते हुए) थे।

मुद्दे तथा प्राथमिकताएं

1.64 पिछले सर्वेक्षण में इंगित किए गए निवेश में बढ़ोतरी और विकास में तेजी के उत्साहवर्धक संकेतों को वर्ष 2005-06 में और सुदृढ़ता मिली है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में निवेश (वर्तमान कीमतों पर) वर्ष 2001-02 में 23.0 प्रतिशत से सुस्थिर रूप से बढ़ता हुआ वर्ष 2004-05 में 30.1 प्रतिशत हो गया। इसकी निरन्तर उत्प्लावकता ऋण के और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात की वृद्धि की तीव्र दर; प्राथमिक निर्गमों की संख्या और मूल्य; तथा द्वितीयक बाजारों में शेयरों की कीमतों में तेजी से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 में 8.1 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से अर्थव्यवस्था की यौगिक औसत वृद्धि दर वर्ष 2005-06 में समाप्त होने वाली गत तीन वर्षों की अवधि में 8.0 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है।

1.65 परिस्थितियां पूरी तरह गत तीन वर्षों में अवलोकित विकास में तेजी के निरन्तर बने रहने के पक्ष में हैं। वृद्धि और बचतों के एक लाभकारी चक्र, जो पहले ही क्रियाशील प्रतीत होता है, के आने वाले वर्षों में बने रहने की संभावना है। आय की वृद्धि में तेजी से, विशेषकर अनुकूल जनसांख्यिकीय गतिकी के सुदृढ़ीकरण से, घरेलू बचतों की

दर में वृद्धि होगी। 'निर्भरता अनुपात' में कमी आने और विकास दर के बढ़ने से कामकाजी आयु समूह में लोगों का अनुपात न केवल बढ़ेगा बल्कि उनके पास पूर्ववर्ती पीढ़ियों की अपेक्षा बचत करने के लिए अधिक ऊंची आय भी होगी। इस प्रकार घरेलू बचत दर में और वृद्धि होगी। अपने सुविदित 'गृह-मोह' के चलते घरेलू बचत किसी भी देश में अधिकांश घरेलू निवेश को वित्तपोषित करती हैं। इस प्रकार आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई घरेलू बचत दर से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश दर के समरूप बढ़ने की संभावना है। और बढ़ती हुई निवेश दर आगे और उच्चतर वृद्धि का आधार बनेगी और चक्र को सृदृढ़ करेगी। जैसे-जैसे भारत में निवेश दर और पूर्वी एशियाई देशों में उनके आरम्भिक उत्थान के दौरान निवेश दर के बीच विशाल अंतर कम होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्वी एशियाई देशों में तब अवलोकित दरों के आस-पास की वृद्धि दरें हासिल करना आरम्भ कर देना चाहिए।

1.66 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का प्रतिफल भी, उत्पादन में, और एक बड़ी राष्ट्रीय आय सृजित करने में अर्थपूर्ण ढंग से नियोजित विशाल और युवा श्रमिक बल के रूप में मिलेगा, विशेषकर ऐसे विश्व में जहां बहुत से देश प्रौढ़ समाज बनने की ओर अग्रसर हैं। विभिन्न अनुभवजन्य अध्ययनों के यह सुझाव कि इसकी संस्थागत शक्तियों के चलते, भारत की प्रति व्यक्ति आय अपने वर्तमान स्तर से चार से पांच गुणा होनी चाहिए, मध्यावधि में विकास के लिए शुभ संकेत देता है। अर्थव्यवस्था को सतत उच्च-विकास की राह पर ले जाने के लिए भारतीय कार्यबल और उद्यमियों की सुप्त प्रतिभा के भंडार को उपयोग में लाने के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा खड़ा करने में एक बहु-आयामी चुनौती निहित है।

1.67 समुचित नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से उत्तम अवसंरचना की शीघ्र व्यवस्था करना इस चुनौती का प्रथम और सबसे बड़ा संघटक है। भारत के विकास की संभावनाएं भौतिक अवसंरचना जैसे बिजली, सड़क, पत्तन और हवाई अड्डों के तीव्र से विकास और इन सेवाओं के दक्ष परिदाय के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं।

1.68 एक अनुमान के आधार पर, व्यस्ततम घंटों में लगभग 12 प्रतिशत और औसत रूप में 8 प्रतिशत की बिजली की कमी उपयोगिताओं से हानि हुए उत्पादन के लगभग 50 बिलियन यूनिट अथवा (3 ₹ प्रति यूनिट पर) 15,000 करोड़ रुपए के समकक्ष है। अर्थव्यवस्था में सकल उत्पादन

का 5 प्रतिशत विद्युत-मात्रा का मोटा अनुमान 20 का आपूर्ति-गणक और उससे जुड़ी 3,00,000 करोड़ रुपए की सकल घरेलू उत्पाद-क्षति इंगित करता है; परन्तु इसमें वैकल्पिक-अलबत्ता अधिक खर्चीले-ऊर्जा स्रोतों जैसे कि कैप्टिव पावर के प्रयोग की उपेक्षा होती है। तथापि, विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता प्रमुख रूप से न केवल बड़े उद्योगों के उत्पादन पर, बल्कि कृषि में सिंचाई तथा लघु व मध्यम उद्यमों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

1.69 खनन क्षेत्रक, विशेष रूप से कोयले में मंदी की प्रवृत्ति का प्रतिवर्तित होना, इस संदर्भ में निर्णायक है। कोयला देश की कुल वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा मांग के लगभग 60 प्रतिशत की पूर्ति करता है और समस्त विद्युत के 70 प्रतिशत का उत्पादन करता है। 1971-73 के दौरान राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्रक पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिपत्य बना हुआ है। वर्ष 2004-2005 के दौरान, 5.6 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि से घरेलू कोयले में कमी आई और कई ताप विद्युत संयंत्र सम्पूर्ण वर्ष संकटपूर्ण आपूर्ति के स्तर (3 दिन का फीड स्टॉक) पर रहे। चालू वर्ष में, 10 मी० (घरेलू कोयले के 18 मी० के समकक्ष) के आयात सहित टोस प्रयासों से जहां ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता में सुधार आया है, वहीं कमी की समग्र समस्या बनी हुई है। मूल्य निर्धारण प्रणाली की कठोरता की समस्या जो आंशिक रूप से मांग के सापेक्ष घरेलू आपूर्ति में कमी का कारण बनी और जिसके कारण बिजली की कमी हुई, का आंशिक रूप से ई-मार्केटिंग लागू करके निराकरण किया गया। अप्रैल-नवम्बर, 2005 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड ने ई-मार्केटिंग के जरिए नीलामी द्वारा 10.2 मी० टन कोयले की बिक्री की। परन्तु अभी और अधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आगे और उदारीकरण की आवश्यकता है, जिसमें ये शामिल हैं: कैप्टिव उत्खनन में लगी किसी सहयोजित कोयला खनन कंपनी को किन्हीं अन्य पात्र अंत प्रयोक्ताओं को अधिक्य कोयले का विक्रय करने की अनुमति प्रदान करना; मूल्य आधारित नीलामियों के माध्यम से कैप्टिव उत्खनन के लिए कोयला ब्लॉकों का आबंटन; और कैप्टिव उत्खनन में संयुक्त उद्यमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधों का उदारीकरण।

1.70 आर्थिक विकास में सड़कों का प्रभाव सुविदित है। उदाहरणार्थ, लैटिन अमरीका में प्रति कामगार सड़कों की लम्बाई में दस प्रतिशत वृद्धि से प्रति कामगार सकल घरेलू उत्पाद में लगभग दो प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, समुचित सड़कों के बिना अनाजों से फलों और सब्जियों जैसी खराब होने वाली जिनसों की ओर कृषि के विविधीकरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, एक समर्थकारी अवसंरचना की कमी निर्यात वृद्धि की सबसे महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। विदेश व्यापार नीति 2004-09 में निर्धारित महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पत्तनों की स्थापित क्षमता में 140 प्रतिशत तक की अनुमानित वृद्धि की आवश्यकता है। भारतीय पत्तनों में जलयानों को 3-5 दिन का टर्न-अराउंड समय लगता है जबकि सिंगापुर और हांगकांग में यह केवल 4-6 घंटे है। पर्यटन क्षेत्र को निरन्तर बढ़ावा सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों, यात्री सुविधाओं में सुधार, और लक्षित पर्यटक समूहों पर जोर देने के कार्यक्रमों को जोरदार तरीके से चलाए जाने की आवश्यकता है।

1.71 अवसंरचना के लिए अपेक्षित कुल निवेश की आवश्यकता बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी समिति ने निवेश आवश्यकताओं का अनुमान इस प्रकार लगाया है: वर्ष 2012 तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्रक में 1,72,000 करोड़ रुपए; वर्ष 2010 तक हवाई पत्तनों के लिए 40,000 करोड़ रुपए; और वर्ष 2012 तक पत्तनों के लिए 50,000 करोड़ रुपए। इस निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आने के आशा है। भारत में केवल अवसंरचना क्षेत्रक में ही अगले पांच वर्षों में 150 बिलियन अमरीकी डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को समाहित करने की अनुमानित सम्भाव्यता है। यह महत्वपूर्ण है कि 5 जनवरी, 2006 को निगमित इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड न केवल प्रचालन में आए, बल्कि शीघ्र ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अन्य संसाधनों के पूरक के रूप में पात्र परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से निधियां, विशेष रूप से दीर्घावधिक परिपक्वता के ऋण, प्रदान करना आरम्भ करे।

1.72 भारत में अवसंरचना क्षेत्रकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियों और संस्थाओं को चुस्त दुरस्त करने की आवश्यकता है। बाजार में विभिन्न भागीदारों के सुविधास्तर को बढ़ाने के लिए एक सुपरिभाषित विनियामक ढांचा स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। नियंत्रण के दायरे और विरोधाभासी अधिकारक्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करने और उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, एक उर्जा विनियामक को विभिन्न क्षेत्रकों की सहक्रिया का लाभ उठाने के लिए, संबंधित मंत्रालयों के समन्वय में होना चाहिए।

1.73 वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 में मोटर स्प्रीट और हाई स्पीड डीजल पर बढ़े हुए सड़क उपकरण के माध्यम से वित्तपोषित सड़कों पर बजटीय परिव्यय में बढ़ोत्तरी हुई। लेकिन अवसंरचना, भौतिक और सामाजिक दोनों पर उच्चतर परिव्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश को खोलने के लिए एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार तीव्रतर समेकन की आवश्यकता बनी हुई है। वर्ष 2005-06 के बजट में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में अस्थाई रोक का सहारा लेना पड़ा था जिसने आरम्भ में जबर्दस्त शुरूआतों के बाद गत्यावरोधों के विगत अनुभव के चलते प्रतिवर्तित स्थिति की आशंकाओं को जन्म दिया है। तथापि, राजस्व घाटे में रोक संसाधनों की मांग को समायोजित करने का एकमात्र उपाय है जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत वित्त मंत्री के वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है। समेकन का कार्य वर्ष 2006-07 के बजट में पुनः आरम्भ किया जाएगा और एफआरबीएमए के अंतर्गत राजकोषीय और राजस्व घाटों के अंतिम लक्ष्य वर्ष 2008-09 के समापन वर्ष तक पूरे किए जाएंगे।

1.74 पूर्ववर्ती चार वर्षों में बहुत कम या मामूली वृद्धि के बाद, वर्ष 2004-05 में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वर्ष 1999-2000 के मूल्यों पर 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोग व्यय की इस श्रेणी में सरकार के सभी स्तर शामिल हैं:- केन्द्र, राज्य, स्थानीय प्राधिकरण तथा अर्ध सरकारी निकाय। पूर्ववर्ती चार वर्षों में से प्रत्येक में क्रमोत्तर रूप से अपने निजी प्रतिपक्षी से धीमी गति पर वर्धित होने के पश्चात्, जीएफसीई में वर्ष 2004-05 में पीएफसीई की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हुई। प्रवृत्ति में यह प्रतिवर्तन अनिवार्यतः चिंता का विषय नहीं है। यदि जीएफसीई में ऐसी वृद्धि समनुरूप परिणामों द्वारा समतुल्य की गई सामाजिक अवसंरचना पर वर्धित परिव्ययों के कारण है। इसके अतिरिक्त पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सामान्य सरकार का राजकोषीय घाटा पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में बढ़कर वर्ष 2001-02 में 9.9 प्रतिशत के चरम स्तर पर पहुंच गया। छठे वेतन आयोग के आसन्न गठन की घोषणा के साथ ही, मध्यावधि में इस प्रकार स्थिति बिगड़ने के दोहराव से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

1.75 हाल के वर्षों में सरकारी पेंशन देयताओं में तीव्र वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में 1 जनवरी, 2004 से परिभाषित अंशदान और बेहतर निवेश विकल्प पर आधारित नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) को लागू करना एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है।

भारत अन्य कई देशों की तुलना में अपनी जनसांख्यिकीय गतिकी के कारण संतुलित पेंशन प्रणाली जो न्याय संगत और सक्षम है की संरचना करने में बेहतर स्थिति में है। 26 जुलाई, 2005 को संसद में प्रस्तुत किया गया, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में उठाए गए सुरक्षोपायों संबंधी चिन्ताओं का समाधान और विधेयक को पारित किया जाना, नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए संस्थागत आधार प्रदान करेगा।

1.76 जबकि शुल्कों के यौक्तिकीकरण, करों की दरों में कटौती और अन्य सुधारों, जिसमें प्रक्रियात्मक सुधार की शामिल है, में उल्लेखनीय प्रगति की गई है, कर प्रणाली में सुधार का कार्य अभी तक अधूरा है। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होने के लिए भारतीय उद्योग जगत को उच्च स्तर के करों और विकृति मूलक छूटों, जिससे प्रतिकूल प्रोत्साहन मिलता है, से भारमुक्त करने की आवश्यकता है। वापस लेने अथवा छूटों को संरक्षण देना बंद करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अपरिवर्तित अथवा कम दरों पर भी अधिक राजस्व प्रोद्भूत हुआ है। कर प्रशासन का सरलीकरण और डिजीटीकरण, जो आरंभ किया जा चुका है, पारदर्शी और कानूनी बाधरहित कर प्रणाली की पूर्वापेक्षा बना हुआ है।

1.77 वर्ष 2005-06 के लिए बजट में सार्वजनिक व्यय में धनराशि का मूल्य सुनिश्चित करने हेतु तंत्र की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए 25 अगस्त, 2005 को परिणाम (आउटकम) बजट राष्ट्र के समक्ष पेश किया गया। यह अणुवीक्षणीय संकेतकों के जरिए कार्यचालन ढांचे की व्यवस्था करता है और यह आगामी वित्तीय वर्ष से लागू होगा। इससे सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम के साथ ही देश भर में विभिन्न शासकीय संरचनाओं से होने वाली प्रमुख उपलब्धियों के बैचमार्क के माध्यम से निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आम नागरिकों को अधिकार प्राप्त होने की आशा है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि निष्पादन संबंधी जटिलताओं और पहले की शून्य आधारित बजट व्यवस्था से बचा जाए, और आउटकम बजट का अक्षरक्षः ही नहीं अपितु इसकी भावना का भी पालन किया जाए।

1.78 लोक वित्त के परिपेक्ष्य में, पेट्रोलियम उत्पादों का उपयुक्त मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण है, विशेषतया सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वर्चस्व वाले पेट्रोलियम विपणन के संबंध में। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में बाजार द्वारा निर्धारित, मूल्य निर्धारण की दिशा में बढ़ते कदम घरेलू एलपीजी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किरोसीन में सब्सिडी के

मुद्दे के लंबित रहते लड़खड़ाने लगे हैं। कच्चे तेल की अधिप्राप्ति और शोधनशाला की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि होने के बावजूद 1 अप्रैल 2002 से किरोसीन की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

1.79 पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सरकार के कुल सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क संग्रहणों का लगभग 40 प्रतिशत है। इसी प्रकार के समतुल्य अधिक बिक्री कर जो 12 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के दायरे में है, पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल के खुदरा मूल्य का कर संघटक अधिक बना हुआ है। अंत-उपयोग के आधार सहित विभिन्न उत्पादों के बीच शुल्क अन्तरों के कारण यह समस्या अधिक जटिल हुई है जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की अदला-बदली और दूसरे कदाचारों की समस्या आयी है। पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य लेवियों में एकरूपता लाने के मुद्दे पर वेट संबंधी राज्य मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है। डा० सी० रंगराजन की अध्यक्षता में पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य निर्धारण तथा कराधान के संबंध में गठित समिति ने मूल्य निर्धारण के लिए हाल ही में एक नए तंत्र की सिफारिश की है जो एक ओर हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में कार्य कुशलता को प्रोत्साहित करती हैं और दूसरी ओर इनमें उपभोक्ताओं के लिए कुकिंग ईंधन के मूल्यों की वहनीयता बनाए रखने की चिन्ता की गई है। कच्चे तेल की कीमतें अधिक बनी रहने की मध्यमावधि संभावनाओं को देखते हुए समस्या के निदान की आधी-अधुरी चेष्टाओं को तेल कंपनियों और राजकोष के वित्तीय हालत पर गंभीर परिणामों के बिना बनाए रखना संभव नहीं है। इसके अलावा ईंधन की अदला-बदली के लिए कदाचार पूर्ण प्रोत्साहन और कर दरों में अन्तर से उत्पन्न विकृतियों का समाधान आवश्यक है। चिरकालिक तेल संकट के प्रबंधन के लिए दृढ़ संकल्प के साथ तुरन्त और साहसिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

1.80 60वें एनएसएसओ के जनवरी-जून 2004 में जो बेरोजगार दरें दर्शाई गई हैं वे कुछ चिन्ता का विषय है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा अधिदेशित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) का 7 सितम्बर, 2005 को अधिनियमन, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो रोजगार की मांग करता है और जो कौशल रहित शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है, 100 दिनों की मजदूरी का रोजगार देना सुनिश्चित किया जाता है, एक ऐतिहासिक पहल है। यदि सक्षमतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए तो एनआरईजीएस ग्रामीण क्षेत्रों में

बेरोजगारी की स्थिति का निर्णायक रूप से निराकरण करेगा और वास्तविक रूप से देश में निर्धनता-परिदृश्य में बदलाव लाएगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित और अच्छी गुणवत्ता की परिसंपत्तियां सुनिश्चित करने हेतु परियोजनाओं का चयन भी महत्वपूर्ण है। एनआरईजीएस के एक व्यापक आधार वाले सुरक्षा नेट के रूप में कार्य करने से निर्धनता उन्मूलन उपायों पर आधारित व्यय के समस्त दायरे का पुनः निर्धारण करने की आवश्यकता है।

1.81 दिन प्रतिदिन के आधार पर रोजगार देने के दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रमों को विकास के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था की उत्पादक प्रक्रियाओं में स्थाई और अच्छी गुणवत्ता की नौकरियों के सृजन में परिवर्तित किया जाना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में श्रम सुधार, विशेषतया उद्योग और निर्यातोन्मुखी क्षेत्र में, निवेश त्वरित करना एक महत्वपूर्ण अधूरा एजेंडा है। घरेलू अर्थव्यवस्था में आईटी पूंजी के क्षेत्र में कम निवेश की समस्या का निराकरण करके उत्पादकता में अभिवृद्धि हो सकती है और रोजगार की संभावना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त बैंक ऋण के प्रावधान को सुविधाजनक बनाकर और पर्याप्त अवसंरचना द्वारा तथा लघु उद्योग के लिए आरक्षण के दायरे से तेजी से मदों को हटाकर मानक सीमाओं को हटाने के जरिए लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास के लिए सशक्त कार्य करने की आवश्यकता है। लघु और मध्यम उद्यमों और कृषि के लिए निर्देशित आर्थिक सहायता प्राप्त ऋण के तहत सामाजिक दायित्व के रूप के स्थान पर लाभ के लिए सुअवर के रूप में देखने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए निदर्शनात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

1.82 स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों के अन्य दायरों में बहुत सी बड़ी पहलें की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई है। वर्ष के दौरान प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र का आबंटन बहुत अधिक बढ़ाया गया है। तथापि, अब यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों के प्रतिफल पर बल दिया जाए और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए न कि उनकी मात्रा या विस्तार पर। उदाहरणार्थ प्राथमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर न कि सिर्फ पहुंच अथवा स्कूल में बच्चों के नामांकन पर दिशानिर्देशों में उपयुक्त परिवर्तन करके उन्हें क्रियान्वित करने के माध्यम से बल देने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्कूल

पद्धति से उतीर्ण हुए बच्चों को अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में योगदान करने का बेहतर अवसर मिले। यद्यपि अधिकांश राज्यों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में व्यापक विस्तार किया गया है, पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है।

1.83 सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के सक्षम प्रबंधन और वितरण के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त क्षमता निर्माण, क्रियान्वयन का विकेन्द्रीकरण, वितरण में पारदर्शिता तथा इसमें लगी एजेंसियों की जवाबदेही आवश्यक हो जाती है। मूल्यांकन अध्ययन बारंबार दर्शाते हैं कि केवल उन्हीं कार्यक्रमों को सफलता मिलती है जिनमें उपर्युक्त महत्वपूर्ण सफलता के मानदंड निहित होते हैं। वर्ष 2005-06 के बजट में यह बल दिया गया है कि सभी आयोजना स्कीमों की जांच पांच वर्षों में एक बार मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और केवल तभी वे आगामी आयोजना में आगे बढ़ाने के लिए पात्र होंगी।

1.84 जबकि तेजी से बढ़ता आयातों तथा मुखरित होते चालू खाता घाटे की चिन्ता कुछ हद तक असंगत लगती है, मुद्रास्फीति, ब्याज दर और राजकोषीय स्थिति से अन्यथा अच्छे आर्थिक परिदृश्य के लिए जोखिम होने की संभावना है। भारत जैसी पूंजी अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था में चालू खाता अधिशेष अपर्याप्त निवेश का लक्षण है। निवेश में अभिवृद्धि करने की स्पष्ट आवश्यकता है। उच्च निवेश के परिणामस्वरूप उच्च बुनियादी मध्यस्थ और पूंजीगत माल आयातों तथा व्यापार एवं चालू खाता घाटा होने की संभावना है। तथापि, इस प्रकार के घाटे से भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है क्योंकि स्वर्ण और चांदी को छोड़कर, गैर-तेल आयातों का वस्तु-संघटन पूंजीगत और अन्य अनिवार्य निविष्टियों के पक्ष में झुका हुआ है और इससे भविष्य में निर्यात की गति बढ़ने की संभावना है।

1.85 उच्च एवं अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतें न केवल भारत अपितु वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी मुद्रास्फीति के परिदृश्य में अनिश्चिता उत्पन्न करती हैं। आयातित कच्चे तेल पर बढ़ती निर्भरता और खुलेपन में वृद्धि होने से भारत कीमत संबंधी घटनाक्रम में विश्व के अन्य देशों से अलग नहीं है। इस मुद्रास्फीति की अनिश्चिता और उलझे हुए वैश्विक वृहद आर्थिक असंतुलनों का प्रभाव ब्याज दर परिदृश्य पर पड़ता है। वैश्विक ब्याज दरों के एक बिन्दु के परे स्थिरीकरण से घरेलू निवेश के उछाल में कमी आने का जोखिम होता है।

1.86 राजकोषीय जोखिम, केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर इस तर्क के कारण उत्पन्न होता है कि भारत में राजकोषीय समायोजन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप गलत प्रकार का व्यय सम्पीड़न हुआ है। इस तर्क से बचना महत्वपूर्ण है क्योंकि समाधान घाटा बढ़ाने में नहीं है अपितु व्यय की गुणवत्ता सुधारने में आने वाली चुनौती का सामना करने में है। विगत के विस्तारात्मक राजकोषीय नीतियों का परिणाम वर्तमान व्यय परिदृश्य के रूप में है और भारी राजकोषीय घाटे के माध्यम से इसको सुधारने का कोई भी निदान कटौती की व्यवस्था है। यद्यपि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम के अधीन कोई अनुल्लंघनीय दण्ड व्यवस्था नहीं है, एक वैश्वीकृत

वातावरण में आशाजनक आर्थिक परिदृश्य के होते राष्ट्र प्रतिकूल परिणामों के बिना अपने राजकोषीय संकल्प से पीछे हटने का दुर्प्रयास नहीं कर सकता है। सतत आर्थिक विकास और स्थिरता की प्रक्रिया बहुत लम्बी है और विस्तारात्मक नीतियों के माध्यम से अस्थायी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर राजकोषीय घाटे के लिए आनन-फानन में समाधान बढ़ती हुई उत्पादकता क्षमता के बावजूद, प्रतिकूल सिद्ध हो सकती हैं। इसके स्थान पर व्यय में बेहतर उत्पादकता और सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर अधिक वृद्धि लाभांश की बहुत अधिक संभावना है जिससे अधिक बचतों और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।